

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण धारक राष्ठीय | ६० दिनों का त्रैक | बेगलूर और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित



5 राहुल गांधी रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को कर रहे हैं गुमराह : भाजपा

6 बढता हुआ कोलेस्ट्रॉल स्वास्थ्य के लिए घातक

7 सुरक्षा परिषद, डब्ल्यूटीओ में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है बिक्स - बिरला

फास्ट टैक

राजनाथ एम्स में मर्ती, हालत स्थिर

नई दिल्ली/एजेन्सी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तबीयत खराब होने के बाद बृहस्पतिवार तड़के यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है। सुबह के अनुसार सिंह को तड़के तीन बजे कमर में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया जहां न्यूरो सर्जरी विभाग में उनका उपचार किया जा रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर निरंतर नजर रखे हुए हैं और अभी उनकी हालत स्थिर बताई गई है।

जदयू ने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग दोहराई

पटना/एजेन्सी। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। जदयू के वरिष्ठ नेता एवं बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने गुस्वारा को राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग दोहराते हुए यहां संवाददाताओं से कहा कि भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से बिहार प्राकृतिक संसाधनों से वंचित है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रमुख सहयोगी जदयू लंबे समय से यह मांग कर रहा है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चौधरी ने कहा कि बिहार में न तो कोई खदान न खनिज और न ही कोई समुद्रतट है। किसी भी राज्य में सोने की खदान होना न तो सरकार की उपलब्धि है और न ही लोगों की। उन्होंने कहा कि बिहार इतना भाग्यशाली नहीं है कि उसके पास ऐसी कोई खदान हो और यह विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए उपयुक्त मामला है।

इमरान खान की हरकत 'आतंकवादी' के समान :

पाकिस्तानी अदालत लाहौर/भाषा। पाकिस्तान की एक आतंकवादी रोधी अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि नौ नई की हिंसा से जुड़े मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हरकत एक 'आतंकवादी' के समान थी। इसने कहा कि उन्होंने अपनी हिंसा के लिए दबाव बनाने के वारंटे पार्टी नेताओं को सैन्य प्रतिष्ठानों, सरकारी संघियों और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का काम सौंपा। पाकिस्तान तहरीक ए इस्लाम (पीटीआई) के 71 वर्षीय संस्थापक और उनकी पार्टी के सैकड़ों सहयोगियों पर कई मामलों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। इनमें नौ मई 2023 को उनके समर्थकों द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शन के संबंध में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत एक मामला भी शामिल है। अदालत के मामले में खान की गिरफ्तारी के बाद भूकंप हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरे पाकिस्तान में प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले किए गए थे।

12-07-2024 13-07-2024
सूर्योदय 6:50 बजे सूर्यास्त 6:00 बजे

BSE 79,897.34 NSE 24,315.95
(-27.43) (-8.50)

सोना 7,599 रु. चांदी 94,850 रु.
(24 केन्ट) प्रति ग्राम प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com



चरम अहिंसक

चींटी तक को बिना बात, मारा हो हमको याद नहीं। कर दें दुश्मन को क्षमा स्वयं, दायर करते प्रतिवाद नहीं। फांसी देने में भी विलंब, सेवक हैं हम सख्याव नहीं। हो गए अहिंसक अब इतने, जेलों तक में जलाव नहीं।

सेवानिवृत्त अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/एजेन्सी। विपक्ष की अग्निवीर योजना को रद्द किये जाने की मांग के बीच सरकार ने कहा है कि सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिये सभी अर्धसैनिक बलों में सिपाहियों के 10-10 प्रतिशत पद आरक्षित किये जायेंगे, साथ ही उन्हें शारीरिक जांच और उम्र में भी छूट दी जायेगी।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल और रेलवे सुरक्षा बल जैसे अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों ने बृहस्पतिवार को बताया कि उन्होंने सेवानिवृत्त अग्निवीरों की भर्ती के संबंध में सभी तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिये बलों में सिपाहियों के 10-10 प्रतिशत

शारीरिक जांच और उम्र में भी अग्निवीरों को छूट दी जायेगी।



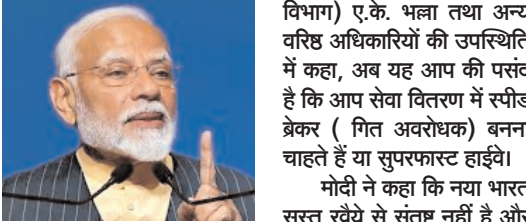
पद आरक्षित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षण में कुछ छूट दी जायेगी, साथ ही उन्हें आयु में भी छूट दी जायेगी। पहले बच के अग्निवीरों को पांच वर्ष की और इसके बाद के बच को उम्र में तीन वर्ष की छूट दी जायेगी। उन्होंने कहा कि दोनों बल यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवानिवृत्त अग्निवीरों को भर्ती में इन छूट का अधिक से अधिक लाभ मिले।

अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षण में छूट पर सरकार की ओर से कहा गया है कि अग्निवीरों की भर्ती के समय उनका शारीरिक परीक्षण किया जाता है और जिसके पास यह परीक्षण प्रमाण पत्र होगा, उसे छूट दी जा सकती है। अधिकारियों ने कहा कि सेनाओं में प्रशिक्षित अग्निवीर मिलने से दोनों बलों की क्षमता और दक्षता बढेगी।

मोदी ने नए आईएस अधिकारियों को बदलाव का उत्प्रेरक एजेंट बनने को कहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/एजेन्सी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुस्वारा को राजधानी में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएस) 2022 बच के 181 अधिकारी प्रशिक्षणों से बातचीत की और उन्हें देश में स्वस्थ बदलाव के उत्प्रेरक एजेंट की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। इन अधिकारियों को केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में शामिल किया गया है। उनके साथ यह बैठक सुषमा स्वराज भवन में आयोजित की गयी। प्रधानमंत्री ने



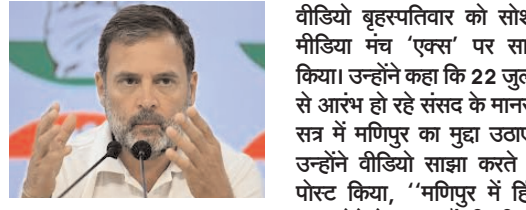
उनको संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें उत्प्रेरक एजेंट बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए और जब वे अपनी आंखों के सामने बदलाव होते देखेंगे तो उन्हें संतुष्टि महसूस होगी। उन्होंने कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गोवा, और सचिव (गृह और कार्मिक एवं प्रशिक्षण

विभाग) ए.के. भन्ना तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कहा, अब यह आप की परसंद है कि आप सेवा वितरण में स्पीड ब्रेकर (गित अवरोधक) बना चाहते हैं या सुपरकार्ट हाईवे। मोदी ने कहा कि नया भारत सुरत रवेय से संतुष्ट नहीं है और सक्रियता की मांग करता है और अधिकारियों को चाहिए कि वे सभी नागरिकों को सर्वोत्तम संभव सुशासन, विनिर्माण की गुणवत्ता और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करें। मोदी ने कहा कि उनके लिए राष्ट्र प्रथम केवल एक नारा नहीं बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य है और उन्होंने अधिकारियों से इस यात्रा में उनके साथ चलने का आह्वान किया।

मणिपुर आज भी बंटा हुआ है, प्रधानमंत्री राज्य का दौरा कर शांति की अपील करें : राहुल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि 'मणिपुर की स्थिति में आज भी सुधार नहीं हुआ है और वह दो टुकड़ों में बंटा हुआ है', ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राज्य का दौरा कर लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए और शांति की अपील करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल



अलायंस' (इंडिया) के घटक दल मणिपुर में शांति की जरूरत को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाकर, सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएंगे। राहुल गांधी ने गत सोमवार को मणिपुर का दौरा कर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। उन्होंने अपने इस दौरे का एक

वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा किया। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र में मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने वीडियो साझा करते हुए पोस्ट किया, 'मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद, मैं तीसरी बार यहां आ चुका हूँ, मगर अफसोस स्थिति में कोई सुधार नहीं है - आज भी प्रदेश दो टुकड़ों में बंटा हुआ है। पर जल रहे हैं, मासूम ज़िंदगीयां खतरे में हैं और हजारों परिवार राहत शिविर में जीवन कानटे पर मजबूर हैं।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को खुद

लोकतंत्र में सब कुछ ठीक नहीं, सभी दलों को आत्मचिंतन की जरूरत : उपराष्ट्रपति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखंड ने बृहस्पतिवार को दुख जताते हुए कहा कि देश में लोकतांत्रिक राजनीति एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गयी है और उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आत्मचिंतन करने का आह्वान किया। राज्य विधान परिषद के शताब्दी समारोह के अवसर पर महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए धनखंड ने यह भी कहा कि लोकतंत्र बहस और संवाद से पनपता है, लेकिन वर्तमान में राजनीतिक दलों के बीच संवादहीनता है।

उपराष्ट्रपति ने कहा, लोकतांत्रिक राजनीति एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गयी है और सभी राजनीतिक दलों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता



है। उन्होंने कहा, संसदीय लोकतंत्र में सब कुछ ठीक नहीं है। हम व्यवधान झेल रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच संवादहीनता है। राज्यसभा के सभापति धनखंड ने कहा कि सदन में आसन के सामने हंगामा और नारेबाजी किसी भी पीठासीन अधिकारी के लिए पीड़ादायक स्थिति है। उन्होंने कहा कि सभापति और अध्यक्ष को दोनों पक्षों द्वारा अपनी सुविधा से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिष्टाचार और अनुशासन लोकतंत्र

सदन में आसन के सामने हंगामा और नारेबाजी किसी भी पीठासीन अधिकारी के लिए पीड़ादायक स्थिति है। सभापति और अध्यक्ष को दोनों पक्षों द्वारा अपनी सुविधा से निशाना बनाया जा रहा है। शिष्टाचार और अनुशासन लोकतंत्र अधिकारी का सम्मान किया जाना चाहिए।

का हृदय हैं और पीठासीन अधिकारी का सम्मान किया जाना चाहिए। धनखंड ने कहा, हम दूसरे दृष्टिकोण के प्रति भी उदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पार्टियां अक्सर सौहार्दपूर्ण नजरिये के बजाय टकराववादी और विरोधात्मक दृष्टिकोण अपनाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नैतिकता और सदाचार भारत में सार्वजनिक जीवन की पहचान हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राज्य विधानसभाएं और संसद लोकतंत्र के उत्तरी ध्रुव हैं, जबकि विधायक और सांसद इसके

प्रकाश स्तंभ हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सत्ता पक्ष पीठासीन अधिकारी के आसन के दायीं ओर होता है, लेकिन मानव शरीर में हृदय बायीं ओर होता है और इसी से आसन की कार्यवाहनी निर्धारित होनी चाहिए। महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी समारोह को उल्लेखनीय मील का पत्थर बताते हुए धनखंड ने 17वीं शताब्दी के प्रतिष्ठित शासक छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद किया।

नीट-यूजी लीक मामला:

सीबीआई ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही शुरू होने के बाद से परार एक कथित आरोपी को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने बिहार के नालंदा से संबंध रखने वाले और मुख्य आरोपी संजीव मुखिया का रिश्तेदार बताया जा रहे रॉकी उर्फ राकेश रंजन को पटना के बाहरी इलाके से पकड़ लिया। सीबीआई मामले की जांच संभालने के बाद से ही उन्होंने उसकी तलाश कर रही थी। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

स्वागत



भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने बृहस्पतिवार को ब्राजील के न्यायाधीश एंतोनियो हर्नन बेंजामिन का स्वागत किया तथा उन्हें 'भारत का अच्छ मित्र' बताया। न्यायमूर्ति बेंजामिन भारत की यात्रा पर आए हैं। उन्होंने सीजेआई तथा उच्चतम न्यायालय के दो अन्य न्यायाधीशों के साथ मंच साझा किया तथा न्यायिक प्रक्रियाएं देखीं। न्यायमूर्ति बेंजामिन का जुलाई में ब्राजील के उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश बनना तय है।

नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर 18 को सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह विवादों से घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर 18 जुलाई को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेवी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार और नीट-यूजी का आयोजन करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शीर्ष अदालत के आठ जुलाई के निर्देश के अनुसार अपना-अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है।

गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज आएगा फैसला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन जवाब मांगा था। आम आदमी निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 12 जुलाई की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ फैसला सुनाएगी। पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका

पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को धनशोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से धनशोधन मामले में प्रवर्तन जवाब मांगा था। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नौ अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और जांच में उनके शामिल होने से बार-बार इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था।

भारत ने बिस्मटेक समूह में नई ऊर्जा भरने पर जोर दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत ने बृहस्पतिवार को सात देशों के बिस्मटेक समूह से बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई ऊर्जा, संसाधन और नई प्रतिबद्धता का आह्वान किया। यह अपील विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राष्ट्रीय राजधानी में दो दिवसीय सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिस्मटेक) सदस्य देशों के अपने समकक्षों की मेजबानी करते हुए की। पहले दिन के विचार-विमर्श में संपर्क, व्यापार और व्यवसाय में सहयोग, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष में सहयोग, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण तथा सामाजिक आदान-प्रदान को शामिल किया गया।



बिस्मटेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के सात देशों को बहुआयामी सहयोग के लिए एक साथ लाता है। भारत के अलावा बिस्मटेक में श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमा, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। जयशंकर ने कहा कि बिस्मटेक को उच्च आकांक्षाएं रखनी चाहिए। जयशंकर ने सम्मेलन के पहले दिन अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा, भारत के लिए बिस्मटेक उसके 'पड़ोस प्रथम' दृष्टिकोण, 'पूर्व की ओर देखो नीति' और 'सागर' दृष्टिकोण के अहम पड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, इनमें से प्रत्येक प्रयास बंगाल की खाड़ी पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रस्तावित किया जा रहा है, जहां सहयोगात्मक क्षमता का लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, हमारी चुनौती इसे बेहतर बनाने की है, और ऐसा तेजी से करना है। बिस्मटेक को क्षेत्रीय सहयोग के लिए

एक जीवंत मंच बनाने के लिए भारत ठोस प्रयास कर रहा है, क्योंकि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के तहत पहल विभिन्न कारणों से आगे नहीं बढ़ रही थी। भारत, 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) की व्यापक नीति रूपरेखा के अंतर्गत हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग कर रहा है। बिस्मटेक विदेश मंत्रियों की बैठक का उद्देश्य खुले तौर पर, स्पष्ट और फलदायी ढंग से विचारों का आदान-प्रदान करना है। जयशंकर ने कहा, बैंकॉक में पिछले सम्मेलन से हम सभी को लाभ मिला था। अब इस सम्मेलन का विशेष महत्व है क्योंकि यह इस वर्ष के अंत में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए मजबूत परिणाम तैयार करने का काम करेगा। उन्होंने कहा, हमारा संदेश स्पष्ट होना चाहिए - कि हम सभी बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच सहयोग में नई ऊर्जा, नए संसाधन और नई प्रतिबद्धता लाने के लिए कृतसंकल्पित हैं।

जयशंकर ने म्यांमार के विदेश मंत्री से कहा

म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का समर्थन करता है भारत

नई दिल्ली/भाषा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बृहस्पतिवार को म्यांमार के अपने समकक्ष यू थान स्वे से कहा कि भारत म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का समर्थन करता है। साथ ही उन्होंने म्यावाड़ी शहर में साइबर घोटाले में शामिल गिरोहों द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिए गए भारतीयों की शीघ्र वापसी पर भी जोर दिया। यू थान स्वे के साथ बैठक में जयशंकर ने भारत-म्यांमार सीमा पर अवैध मादक पदार्थों के प्रवाह, हथियारों के व्यापार और विद्रोही समूहों की गतिविधियों का मुद्दा भी उठाया। यह वार्ता दिल्ली में बिस्मटेक समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई। जयशंकर ने 'एक्स' पर कहा, बिस्मटेक विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान म्यांमार के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री यू थान स्वे से मुलाकात की। सीमा स्थिरता और विस्थापित लोगों के प्रवाह के संबंध में अपनी चिंताओं को साझा किया। उन्होंने कहा, इसके अलावा अवैध मादक पदार्थों और हथियारों के व्यापार तथा उखावादी समूहों की गतिविधियों के मुद्दों पर भी बात की गई। साइबर घोटाले करने वाले गिरोहों द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिए गए भारतीयों की शीघ्र वापसी के लिए भी जोर दिया गया।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाएं परिवार नियोजन के विकल्प तय करने में सक्षम हों : जेपी नड्डा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने बृहस्पतिवार को कहा कि 'विकसित भारत' का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भारत के परिवारों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और यह लक्ष्य छोटे परिवारों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं परिवार नियोजन के विकल्प तय करने के अपने



अधिकार का प्रयोग कर सकें और उन पर अनचाहे गर्भधारण का बोझ न पड़े।

'विश्व जनसंख्या दिवस' के अवसर पर नड्डा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ डिजिटल बैठक की। कार्यक्रम की विषय-वस्तु मां और बच्चे की भलाई के लिए गर्भधारण का उचित समय और अंतराल थी।

मंत्री ने कहा कि विकल्प के तौर पर आधुनिक गर्भनिरोधकों की उपलब्धता है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गर्भनिरोधकों को उपलब्ध कराने के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर किया जाए, विशेष रूप से अधिक (जनसंख्या)

बोझ वाले राज्यों, जिलों और प्रखंडों में। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि विश्व की जनसंख्या का पांचवां हिस्सा भारत का है, जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में कार्य करने की पुनः पुष्टि और प्रतिबद्धता के रूप में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

नड्डा ने कहा, विकसित भारत का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भारत के परिवारों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, जिसे छोटे परिवारों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्यों को सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत है ताकि यह

सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं परिवार नियोजन के विकल्प तय करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और उन पर अनचाहे गर्भधारण का बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य 'अपनी इच्छा से और स्वीजिड निर्णय द्वारा जन्म' होना चाहिए।

युवाओं, किशोरों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित सभी के लिए एक उज्वल, स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने पर सरकार के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए मंत्री ने कहा, सहयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आगामी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और परिवार नियोजन और

प्रजनन स्वास्थ्य को मौलिक मानते हैं। नड्डा ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफल योजनाओं में से एक 'मिशन परिवार विकास' (एमपीवी) पर बात की, जिसे शुरू में सात उच्च फोकस वाले राज्यों के 14 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (एचपीडी) के लिए शुरू किया गया था और बाद में इन राज्यों और छह पूर्वोत्तर राज्यों के सभी जिलों को कवर करने के लिए इसका विस्तार किया गया। उन्होंने योजना के प्रभाव पर जोर दिया और इन राज्यों में गर्भनिरोधकों तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि तथा मातृ, शिशु और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में सफलतापूर्वक

कमी को रेखांकित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जिलों को इस योजना का प्राथमिक केन्द्र बिन्दु बनाने से पूरे राज्य में टीएफआर (कुल प्रजनन दर) को नीचे लाने में मदद मिली। मिशन परिवार विकास ने न केवल राज्यों की टीएफआर को कम करने में योगदान दिया है, बल्कि राष्ट्रीय टीएफआर कम करने में भी मदद की है। उन्होंने कहा, हमें उन राज्यों में कम टीएफआर बनाए रखने की दिशा में काम करने की जरूरत है, जिन्होंने इसे पहले ही हासिल कर लिया है, तथा अन्य राज्यों में भी इसे हासिल करने की दिशा में काम करना होगा।



पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को 22 हजार सीआरएम मशीन दी जाएंगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बंजीमद/भाषा। पंजाब सरकार राज्य के किसानों को 22 हजार से अधिक 'फसल अपशिष्ट प्रबंधन' (सीआरएम) मशीन मुहैया कराने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इसी महीने रियायती दर पर मशीन मुहैया कराने के लिए लॉटरी निकाली जाए और अगस्त के आखिर तक लाभार्थी किसानों को सॉल्विडी की राशि दे दी जाए। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए 500 करोड़ रुपये की कार्ययोजना बनाई है। सीआरएम मशीन किसानों को खरीफ सत्र 2024-25 में रियायती दर पर दी जाएगी। उन्होंने कहा, 'किसान इन मशीनों के लिए 50% सॉल्विडी प्राप्त कर सकते हैं जबकि पंचायत और सहकारी समितियों के लिए सॉल्विडी 80% तक की गई है।'

ईडी ने 25,000 करोड़ रुपए की बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में कंपनी प्रवर्तक को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 25,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत एक दिवालिया ऑटोमोटिव उपकरण विनिर्माण कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। निदेशालय ने एक बयान में बताया कि 'एमटेक' समूह के निदेशकों में शामिल और कंपनी के प्रवर्तक अरविंद धाम को मंगलवार (नौ जुलाई) को हिरासत में लिया गया। धाम को दिल्ली में एक विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएनएलए) अदालत के समक्ष बुधवार को पेश किया गया जिसने उसे सात दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ धनशोधन का मामला सीबीआई की नौ प्रार्थनाओं से सामने आया है जो आईसीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की लिखित शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई थी। एजेंसी ने बताया कि यह आरोप लगाया गया था कि धोखाधड़ी, जालसाजी और आलापिक विश्वासघात करके ऋणों का इस्तेमाल कर्हीं और किया गया, जिससे बैंकों को गलत तरीके से 673.35 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

नक्सलवाद पर लगाम लगाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया विधेयक

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र सरकार ने व्यक्तियों और संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसके बाद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोर देकर कहा कि प्रभावी कानूनी माध्यमों से ग्रामीण और शहरी इलाकों में नक्सली संगठनों की बढ़ती मौजूदगी पर शिकंजा कसने की जरूरत है। 'महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024' नामक इस विधेयक को शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद और उसके समर्थकों से होने वाले खतरों पर अंकुश लगाने के लिए अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में गैरकानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम के लिए जन सुरक्षा अधिनियम बनाए हैं।

महिला नक्सली समेत चार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

सुकमा/भाषा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में एक महिला नक्सली समेत चार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चार

नक्सलियों दिवदो हिडमा (39), महिला नक्सली सोडी सोमे (30), पोड़ियाम हुंगा (25) और मुचाकी देवा (55) ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने बताया कि नक्सली दिवदो हिडमा पर एक लाख रुपये का इनाम है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ सरकार की 'नियत नेवला नार' (आपका अच्छा गांव) योजना से प्रभावित होकर तथा बाहरी नक्सलियों द्वारा

भेदभाव से तंग आकर आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ पुलिस दल पर हमला, मार्गों को काटना और नक्सली पर्व लगाने जैसे कार्यों में शामिल होने का आरोप है।

अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाएगी।

गुजरात में गुणवत्ता को बनाएंगे विकास की आधारशिला : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अहमदाबाद/भाषा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य गुणवत्ता को पूरी सफलता से अपनाने और इसे राज्य में विकास की आधारशिला बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पटेल ने गुजरात में गुणवत्ता को लेकर प्रतिबद्धता जताने वाली पहल 'गुणवत्ता संकल्प गुजरात' की शुरुआत के मौके पर यह बात कही। भारतीय गुणवत्ता परिषद (व्यूसीआई) की इस पहल का उद्देश्य राज्य में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गुणवत्ता हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करना है।

एक बयान के मुताबिक, 'गुणवत्ता संकल्प गुजरात' पहल का उद्देश्य गुणवत्ता हस्तक्षेपों के माध्यम से राज्य सरकार की पहल को बढ़ाना और उनका समर्थन करना, जमीनी स्तर पर गुणवत्ता की बुनियाद स्थापित करना और अमृत काल में 'विकसित गुजरात' के लिए एक समग्र गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि कुछ



साल पहले तक भारत में गुणवत्ता एक बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया जाने वाला शब्द था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश गुणवत्ता की ओर बढ़ रहा है। पटेल ने कहा, 'चाहे मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री ने जो भी आंदोलन शुरू किए हैं, उनमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हम गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम इसे विकास की आधारशिला बनाने में 100 प्रतिशत सफलता हासिल करेंगे।' इस अवसर पर व्यूसीआई के चेयरमैन जयक्य शाह ने कहा, 'इस पहल का उद्देश्य जीवन, आजीविका और उद्योग के हर पहलू में गुणवत्ता के सिद्धांतों को शामिल करना है।

हम साथ मिलकर गुणवत्ता और उत्कृष्टता में नए मानक स्थापित करेंगे, जिससे गुजरात विकसित भारत का पहला विकसित राज्य बनेगा।' 'गुणवत्ता संकल्प' राज्य की सहभागिता पर आधारित पहल है। इसमें व्यूसीआई राज्यों के साथ मिलकर उनकी विकास यात्रा को अखिल भारतीय गुणवत्ता आंदोलन का हिस्सा बनाता है। यह सरकार और उद्योग के हितधारकों को साथ लाता है, बाधाएं दूर करता है और गुणवत्ता का पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए रूपरेखा बनाता है। यह गुणवत्ता संकल्प का पांचवां संस्करण था। इससे पहले उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में इसके संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं।



उत्तराखंड : बद्रीनाथ राजमार्ग अवरुद्ध होने से श्रद्धालु मुसीबत में

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गोपेश्वर/भाषा। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोगीधारा में हुए भूस्खलन के कारण पिछले तीन दिन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के अवरुद्ध होने से हिमालयी धाम तथा हेमकुंड सहित जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने श्रद्धालुओं को लेकर जा रहे वाहनों को चमोली और कर्णप्रयाग के बीच रोक दिया, जिससे लंगरू थाने के निकट जाम जैसी स्थिति बन गयी।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के कर्मी जोगीधारा में मलबे के ढेर को पार करने में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं जबकि वाहनों में यात्रा करने वाले लोग लंगरू थाने के मुख्य मार्ग पर आवाजाही शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। राजमार्ग

के अवरुद्ध होने के कारण बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को हुए मतदान के लिए दूरस्थ स्थानों पर गए चुनावकर्मीयों को भी गोपेश्वर लॉन्ग में भी दिक्कत हुई। जिला निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि चुनावकर्मी द्रोणागिरी, जुम्मा और कोशा जैसे दूरस्थ मतदान केंद्रों से मतदान उपकरणों और सामग्री के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए गोपेश्वर लॉन्ग।

चमोली के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी ने बताया कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) सड़क पर पड़े मलबे को साफ करने में जुटा है हालांकि, पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने के कारण सफाई के कार्य में दिक्कत आ रही है। वहीं मानसून शुरू होते ही भूस्खलन के कारण मार्गों के अवरुद्ध होने से धामों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आयी है। बुधवार को बद्रीनाथ धाम में केवल 400 श्रद्धालुओं ने ही दर्शन किए जबकि मानसून से पहले रोजाना हजारों की संख्या में तीर्थयात्री आ रहे थे।

गोवा पुलिस ने अमिनेता गौरव बख्शी को मंत्री की कार रोकने के आरोप में गिरफ्तार किया

पणजी/भाषा। गोवा पुलिस ने बृहस्पतिवार को अमिनेता गौरव बख्शी को राज्य के पशुपालन मंत्री नीलकंठ हलनकर की कार रोककर उनकी आवाजाही में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वेब सीरीज और कुछ फिल्मों में अभिनय कर चुके बख्शी ने भी इस मामले को लेकर एक शिकायत दर्ज करवायी जिसमें दावा किया कि मंत्री की कार ने उनका रास्ता रोका था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हलनकर के निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) द्वारा उत्तरी गोवा जिले के कोलवले पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद अमिनेता को गिरफ्तार किया गया।

अधिकारी ने बताया कि उन पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि यह घटना उस समय हुई जब वह बुधवार को उत्तरी गोवा जिले के रेवोरा पंचायत कार्यालय में एक समारोह में भाग लेने के बाद चमोली कार से जा रहे थे। मंत्री ने आरोप लगाया कि आरोपी की कार ने उनका रास्ता रोक लिया और जब बख्शी से गाड़ी हटाने को कहा गया तो अमिनेता ने उनके पीएसओ को धमकी दी। बख्शी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्होंने पंचायत कार्यालय में हुई घटना को लेकर स्थानीय पुलिस थाने में मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

दरअसल, मंत्री ने समाचार चैनल सीएनबीसी-टीवी18 से विशेष शक्तिकान्त दास ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुद्रास्फीति की मौजूदा दर और उसे चार प्रतिशत पर लाने के लक्ष्य के बीच अंतर को देखते हुए नीतिगत दर पर रुख में बदलाव के सवाल का अभी कोई मतलब नहीं है। दास ने समाचार चैनल सीएनबीसी-टीवी18 से विशेष शक्तिकान्त दास ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुद्रास्फीति की मौजूदा दर और उसे चार प्रतिशत पर लाने के लक्ष्य के बीच अंतर को देखते हुए नीतिगत दर के मामले में रुख में बदलाव के सवाल का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। '...जब हम टिकाऊ आधार पर खुदरा महंगाई चार प्रतिशत पर लाने की दिशा में बढ़ते तभी हमें रुख में

शिवराज सिंह चौहान ने कृषि के विकास के लिए बिहार के किसानों को पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे को राज्य के किसानों को अटूट समर्थन देने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य के बीच तालमेलपूर्ण प्रयासों की वकालत की। नई दिल्ली के कृषि भवन में आयोजित बैठक में चौहान ने बिहार की कृषि पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना



(आरकेवीआई) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत धन आवंटन का पुनर्मूल्यांकन करने की प्रतिबद्धता जताई। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए नए प्रस्ताव प्रस्तुत



देश के करीब 80% इलाके तक पहुंचा मोबाइल, 4जी का दायरा बढ़ाना प्राथमिकता : संचार मंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंदौर (मध्यप्रदेश)/भाषा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि मोबाइल फोन देश के 70 से 80 फीसद इलाके तक पहुंच चुका है और 4जी नेटवर्क का दायरा बढ़ाना उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है। सिंधिया ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, 'देश के 70 से 80 प्रतिशत इलाके में मोबाइल फोन पहुंच चुका है और फिलहाल ऐसे 120 करोड़ उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब हमारी प्राथमिकता है कि देश में 4जी नेटवर्क का दायरा बढ़ाया जाए।' उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व में पहली बार विश्वेशी तकनीक से '4जी स्टेक' बनाया

है और इसके बूते देश के 100 प्रतिशत इलाके में 4जी नेटवर्क पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सिंधिया के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय भी है। उन्होंने बताया कि वह शुक्रवार से पूर्वोत्तर के राज्यों के दो दिवसीय दौरे की शुरुआत असम और मेघालय से करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम पूर्वोत्तर के राज्यों की खुशियों और क्षमताओं के आधार पर उनके विकास की रणनीति बनाएंगे। इसके लिए संबंधित प्रदेश सरकारों के साथ बैठक करके फैसले किए जाएंगे।' यह पूछे जाने पर कि मणिपुर में जातीय संघर्ष के हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं, सिंधिया ने सीधा जवाब टालते हुए कहा कि वह पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास की अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।

महंगाई के चलते नीतिगत दर रुख में बदलाव के सवाल का अभी कोई मतलब नहीं : दास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुद्रास्फीति की मौजूदा दर और उसे चार प्रतिशत पर लाने के लक्ष्य के बीच अंतर को देखते हुए नीतिगत दर पर रुख में बदलाव के सवाल का अभी कोई मतलब नहीं है। दास ने समाचार चैनल सीएनबीसी-टीवी18 से विशेष शक्तिकान्त दास ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुद्रास्फीति की मौजूदा दर और उसे चार प्रतिशत पर लाने के लक्ष्य के बीच अंतर को देखते हुए नीतिगत दर के मामले में रुख में बदलाव के सवाल का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। '...जब हम टिकाऊ आधार पर खुदरा महंगाई चार प्रतिशत पर लाने की दिशा में बढ़ते तभी हमें रुख में



बदलाव के बारे में सोचने का भरोसा मिलेगा।' उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप लाने का काम उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, लेकिन चार प्रतिशत का लक्ष्य अंतिम पड़ाव है, जो आसान नहीं है। आरबीआई ने जून में पेश द्विमासिक मांद्रिक नीति समीक्षा में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में खुदरा मुद्रास्फीति 4.9 प्रतिशत,

दूसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। केंद्रीय बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। मांद्रिक नीति निर्धारित करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर किया जाता है। दास ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संबंध में कहा कि वृद्धि को गति देने वाले कई तत्व आर्थिक भूमिका निभा रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में आर्थिक वृद्धि की गति बहुत मजबूत थी और यह चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी मजबूत बनी हुई है। आरबीआई ने बढ़ती निजी खपत और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में पुनरुद्धार को देखते हुए पूनर् की मांद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को सात प्रतिशत से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है।

शिवराज सिंह चौहान ने कृषि के विकास के लिए बिहार के किसानों को पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया

कृषि के विकास के लिए बिहार के किसानों को पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्री मंगल पांडे को राज्य के किसानों को अटूट समर्थन देने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य के बीच तालमेलपूर्ण प्रयासों की वकालत की। नई दिल्ली के कृषि भवन में आयोजित बैठक में चौहान ने बिहार की कृषि पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

मंत्री ने राज्यभर में कृषि विज्ञान केंद्रों (केडीके) को मजबूत करने की अनियार्यता पर जोर दिया। चौहान ने उनकी परिचालन क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रतिबद्धता जताई। मन्ना और मखाना उत्पादन में बिहार की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए पांडे ने इन अवसरों को अधिकतम करने के लिए केंद्र से सहायता मांगी। बैठक में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर और केंद्रीय और राज्य कृषि और बागवानी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रियों से मुलाकात की थी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत



56 ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कलबुर्गी। कर्नाटक में गुरुवार सुबह लोकायुक्त की टीम ने कई अधिकारियों और इंजीनियरों के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त टीम कर रही है। कर्नाटक लोकायुक्त की छापेमारी कर्नाटक के 9 जिलों में चल रही है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के 11 मामले शामिल हैं। ये कार्रवाई कर्नाटक के कुल 56 स्थानों पर चल रही है। रेड में करीब 100 अधिकारियों के

शामिल होने की खबर है। जानकारी के अनुसार, लोकायुक्त के अधिकारियों ने बृहत् बंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के केंगरी डिप्टी जेन में तैनात राजस्व अधिकारी बसवराज मागी के कलबुर्गी और बंगलूरु स्थित घरों पर गुरुवार सुबह छापा मारा। इसके अलावा कलबुर्गी शहर में स्थित वीरेंद्र पाटिल बरंगाय के घर पर रेड मारी गई है। सूत्रों के अनुसार, आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर लोकायुक्त अधिकारियों की सुबह से छापेमारी जारी है। लोकायुक्त अधिकारियों द्वारा संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों

का सत्यापन किया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिलने के बाद आरोपी अधिकारियों के घर पर लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा लोकायुक्त अधिकारियों ने मांड्या में ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता प्रभाग के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर भी छापा मारा। साथ ही असिसटेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेण्डेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक तहसीलदार के आवास पर कार्रवाई जारी है। रेड को लेकर अभी तक लोकायुक्त अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले विधायक को कर्नाटक पुलिस ने भेजा नोटिस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बंगलूरु। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार को दक्षिण कन्नड़ जिले से भाजपा विधायक वाई भरत शेड्डी को पृष्ठताछ के लिए नोटिस जारी किया है। शेड्डी ने सोमवार को कांग्रेस सांसद पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनके कथित हिंदू विरोधी बयान के लिए संसद के अंदर बंद कर थप्पड़ मारना चाहिए।

कावूर पुलिस ने शेड्डी को नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों के भीतर पेश होने को कहा है। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351 (3) (आपराधिक धमकी, अपमान), 353 (सार्वजनिक शरारत के लिए बयानबाजी) के तहत मामला दर्ज किया है। इस संबंध में कांग्रेस नेता अनिल कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। शेड्डी ने कहा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद के अंदर बंद कर थप्पड़ मारना चाहिए। ऐसा करने से सात से आठ एफआईआर दर्ज हो जाएंगी। अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलूरु शहर आते हैं तो हम उनके लिए भी यही व्यवस्था



करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भगवान शिव की तस्वीर पकड़े हुए थे। उन्होंने कहा था, पागल को नहीं पता कि अगर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली तो वह (एलओपी) भ्रम हो जाएंगे। उन्होंने हिंदू विरोधी नीति अपनाई है। यह स्पष्ट है कि एलओपी राहुल गांधी एक पागल है। उन्हें लगता है कि वह हिंदुओं के बारे में जो कुछ भी कहेंगे, हिंदू चुपचाप सुन लेंगे।

शेड्डी ने दावा किया कि हिंदू धर्म और संस्थाओं की रक्षा करना भाजपा का कर्तव्य है। कांग्रेस ने यह संदेश देना शुरू कर दिया है कि हिंदू और हिंदुत्व अलग-अलग हैं। ऐसे नेताओं की वजह से भविष्य में हिंदुओं को खतरा होगा। उन्होंने कहा, शिवाजी और महाराणा प्रताप हिंदू समुदाय में पैदा हुए थे। जब भी जरूरत होगी, हम हथियार निकाल लेंगे। हम हथियारों की पूजा करने के बाद क्या करना है, अच्छी तरह से जानते हैं।

क्या राहुल अपने पिता का समर्थन करेंगे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान? : कर्नाटक भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बंगलूरु। कर्नाटक भाजपा ने गुरुवार को पूछा कि क्या राहुल गांधी अपने पिता दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के रुख का समर्थन करेंगे या मुस्लिम महिला भरण-पोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे? भाजपा की राज्य महिला मोर्चा की अध्यक्ष सी. मंजुला ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तब तक दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी का क्या? क्या वह अपने पिता के रुख का समर्थन करेंगे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे? सी. मंजुला ने कहा कि 1985



में जब कांग्रेस बहुमत में थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम महिलाओं को दिए गए न्याय और सम्मान की अवहेलना की थी। उन्होंने कहा, आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है। ट्रिपल तलाक को खत्म करने वाली भाजपा सरकार फिर से

इन महिलाओं के पक्ष में खड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाएं अब ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं।

सी. मंजुला ने आगे कहा कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी 125 के तहत फैसला सुनाया था कि अपने पतियों से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भरण-पोषण पाने की हकदार हैं। हालांकि, दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने संसद में इसका विरोध किया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसा करके उन्होंने संविधान के सिद्धांतों की अवहेलना की। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के महिला-समर्थक रुख के खिलाफ खड़ी है।

करंदलाजे ने गृह मंत्री से वाल्मीकि सहकारी घोटाले की जांच शुरू करने का आग्रह किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बंगलूरु। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है कि वह केंद्रीय एजेंसियों को राज्य के स्वामित्व वाले कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से कोष के अवैध हस्तांतरण की विस्तृत जांच का निर्देश दें। करंदलाजे ने निगम के लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन पी. की आत्महत्या का भी उल्लेख किया, जिसके बाद यह घोटाला सामने आया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, चंद्रशेखरन ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है



कि निगम की 187 करोड़ रुपये की राशि अवैध रूप से हस्तांतरित की गई। इसमें 88.62 करोड़ रुपये कुछ आईटी कंपनियों और हैदराबाद स्थित एक सहकारी बैंक के विभिन्न खातों में स्थानांतरित किए गए। कर्नाटक की बंगलूरु उत्तर

लोकसभा सीट से सांसद करंदलाजे ने कहा कि हो सकता है कि चंद्रशेखरन ने घोटाले के संबंध में डाले जा रहे अत्यधिक दबाव और मिल रही संभावित धमकियों के चलते आत्महत्या की हो।

उन्होंने शाह को लिखे पत्र में कहा, श्री चंद्रशेखरन का जाना एक गहरा सदमा है और उनकी असायिक मृत्यु के कारणों की तत्काल पारदर्शी व गहन जांच की आवश्यकता है। उन्होंने शाह से अनुरोध किया कि वाल्मीकि विकास निगम घोटाले की संबंधित अधिकारियों से व्यापक जांच कराई जाए, ताकि इसमें शामिल सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

'मुड़ा घोटाला' मामले में मुझे अनावश्यक रूप से निशाना बनाया जा रहा है : सिद्धरामैया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैसूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुड़ा) द्वारा भूखंड आवंटित करने में कथित फर्जीबाड़ी के मामले में उन्हें अनावश्यक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का आरोप है कि मुड़ा ने उन लोगों को मुआवजे के तौर पर भूखंड वितरित करने में अनियमितता बरती जिनकी जमीन का "अधिग्रहण" किया गया है। मुआवजे के तौर पर भूखंड प्राप्त करने वालों में सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती भी शामिल हैं। सिद्धरामैया ने दावा किया कि उनके खिलाफ यह साजिश इसलिए रची जा रही है क्योंकि वह पिछड़े वर्ग से आते हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि वह ऐसी साजिशों से नहीं डरेंगे। मुख्यमंत्री भाजपा के प्रदेश



अध्यक्ष बी. याई. विजयेंद्र द्वारा कथित 'घोटाले' के सिलसिले में सिद्धरामैया के गृह जिले मैसूरु में 12 जुलाई को व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करने की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। सिद्धरामैया ने यहां पत्रकारों से कहा, "क्या हमने इसकी (मुड़ा घोटाले की) जांच नहीं कराई

है.... भाजपा राजनीति के लिए काम कर रही है, अगर वे राजनीति करेंगे तो हमें भी राजनीति करनी पड़ेगी। उन्हें किसी के नेतृत्व में ऐसा करने दें, उन्हें जे पी नड्डा (भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष) के नेतृत्व में ऐसा करने दें। यदि वे ऐसा करते हैं, तो हम भी इस मामले को राजनीतिक रूप से लेंगे। क्या

केवल वे ही राजनीति कर सकते हैं? हम यह भी जानते हैं कि इसका राजनीतिक रूप से मुकाबला कैसे किया जाए।" अपनी पत्नी को आवंटित भूखंड को लेकर भाजपा द्वारा उन पर निशाना साधने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, "उन्हें बताना होगा कि ये कहां अवैध है। हम कह रहे हैं कि सब

वैध है। उन्हें यह दिखाने दीजिए कि यह अवैध है।"

उन्होंने कहा, "राजनीति के लिए बेवजह मुझे निशाना बनाया जा रहा है। वे राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। इसलिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। क्या मैं ऐसी साजिशों से डर जाऊंगा?" उन्होंने सवाल किया, "अगर भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान मुड़ा ने गलत काम किया तो सिद्धरामैया इसके लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं?" कार्यकर्ता टी जे अब्बाह द्वारा उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराए जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी पत्नी पार्वती के नाम पर तीन एकड़ और 16 गुंठा जमीन का खुलासा नहीं किया है, सिद्धरामैया ने कहा, "अगर निर्वाचन आयोग नोटिस देता है, तो मैं उसका जवाब दूंगा। कानून के अनुसार जवाब दूंगा।"

बधाई



मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को बंगलूरु में कर्नाटक मीडिया अकादमी की नई अध्यक्ष आयाशा खानम और सदस्य के चैकटेश को बधाई दी।

स्वास्थ्य विभाग के केंद्रों में डेगू मरीजों की मुफ्त जांच होगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बंगलूरु। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डेगू बुखार के मरीजों की जांच होगी और उनका मुफ्त उपचार किया जाएगा। विभाग ने एक परिपत्र में राज्य स्तर पर 'डेगू वार रूम' की स्थापना की घोषणा की। उसने इसी परिपत्र में जिला प्रशासकों से जिला स्तर पर 'डेगू वार रूम', जिला स्तरीय कार्यबल के गठन, अधिक संक्रमण वाले

क्षेत्रों की पहचान, ज्वर क्लीनिक को सक्रिय करने, मच्छर भगाने वाले तरल पदार्थों का वितरण करने जैसे कई दिशानिर्देश दिये और उनका कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया। परिपत्र में कहा गया है, वर्तमान मानसून में राज्य में मौजूदा डेगू स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह बिल्कुल जरूरी है कि उपचार एवं प्रबंधन के सिलसिले में अपनाये जाने वाले उपाय परिणामोन्मुख हों। इस संबंध में दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के भी निर्देश जारी किये गये हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार

कर्नाटक में इस साल जनवरी से इस बुधवार तक डेगू के 7,840 मामले सामने आये हैं जिनमें से सबसे अधिक 2292 मामले बृहत् बंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) क्षेत्र के हैं। राज्य में बुधवार को डेगू के 293 मामले सामने आये जिनमें 118 बीबीएमपी क्षेत्र के हैं। परिपत्र में कहा गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत आने वाले सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डेगू बुखार के सभी मरीजों (वाहे वे बीपीएल में हो या एपीएल) की सभी जांच एवं उपचार (यदि जरूरी हो तो आर्इसीयू भी) मुफ्त की जाएगी।

भाजपा ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव की हार से सबक नहीं सीखा : स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

धर्मपुरी। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तमिलनाडु में बार-बार चुनावी तौर पर शिकस्त खाने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा है और उस पर राज्य में प्रमुख परियोजनाओं के लिए धनराशि मंजूर नहीं करने का आरोप लगाया। स्टालिन ने यहां ग्रामीण क्षेत्रों में 'मकलुदन मुधलवार' (लोगों के साथ मुख्यमंत्री) योजना का विस्तार करते हुए

कहा कि इसके माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि किसी को कोई शिकायत न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के लिए इस तरह के समर्पित कार्य विपक्षी दलों के लिए इच्छा पैदा कर रहे हैं और इसीलिए वे 'दुष्प्रचार' के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए है, चाहे उन्होंने द्रमुक को वोट दिया हो या नहीं, दूसरों में ऐसी उदारता नहीं देखी जा सकती। स्टालिन ने कहा, केंद्र सरकार (भाजपा) ने (2024 के लोकसभा चुनाव में) अपनी चुनावी हार और (राज्य में

पिछले चुनावों में) लगातार हार से सबक नहीं सीखा है। केंद्र सरकार के पास चेन्नई में मेट्रो रेल चरण-दो जैसी तमिलनाडु की प्रमुख परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने का दिल नहीं है और उसने अपने शासन के पिछले 10 वर्षों के दौरान राज्य में कोई भी बड़ी परियोजना लागू नहीं की है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु के लोगों की ओर से यह कहना है कि उन्हें (केंद्र की भाजपा सरकार को) कम से कम अब यह समझ लेना होगा कि केंद्र सरकार में सभी लोगों के लिए समान शासन व्यवस्था होनी चाहिए और उन्हें अपनी पसंद या नापसंद से ऊपर उठना चाहिए।

सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान जा रही प्रतिबंधित रसायनों की वीनी खेप तमिलनाडु के बंदरगाह पर जब्त की

चेन्नई। सुरक्षा एजेंसियों ने तमिलनाडु के एक बंदरगाह पर अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिबंधित रसायनों की चीन से आई एक खेप जब्त की है जो माना जा रहा है कि पाकिस्तान के जैविक और रासायनिक युद्ध कार्यक्रम के लिए थी। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यह खेप ऑर्थो-बलरो बेंजिलिडीन मैलोनोनाइट्राइल या सीएस की थी जिसका इस्तेमाल आंसू गैस और दंगा नियंत्रण एजेंट के रूप में किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों ने तमिलनाडु के कट्टपल्ली बंदरगाह पर इस खेप को रोका था। सीएस अंतरराष्ट्रीय समझौतों और भारत की निर्यात नियंत्रण सूची के तहत दोहरे उपयोग वाला रसायन है। दंगा नियंत्रण एजेंटों के रूप में इसका असैन्य उपयोग होता है, लेकिन जब्त की गई इतनी बड़ी मात्रा इसके संभावित सैन्य उपयोग की आशंका के बारे में चिंता पैदा करती है। अधिकारियों ने कहा कि 25 किलोग्राम के 103 ड्रमों में रखी गयी यह सामग्री 18 अप्रैल, 2024 को चीन के शंघाई बंदरगाह पर मालवाहक जहाज ह्युई शंघाई (साइप्रस) के ध्वज के साथ संचालित) में लदी गयी थी। कराची की ओर जा रहा जहाज आठ मई, 2024 को कट्टपल्ली बंदरगाह पहुंचा।

सुनवाई



मुख्यमंत्री सिद्धरामैया गुरुवार को मैसूरु में अपने आवास पर जनता की समस्याएं सुनते हुए।

वाल्मीकि निगम घोटालेबाजों ने अधिकारियों को मोहपाश में फंसाकर पैसे की हेराफेरी की : भाजपा नेता

बंगलूरु। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता श्रीरामलु ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के घोटालेबाजों ने धन की हेराफेरी करने के लिए सरकारी और बैंक अधिकारियों को मोहपाश में फंसाया है। पूर्व मंत्री ने दावा किया कि आदिवासियों के कल्याण के पैसे से महंगी लक्जरी गाड़ियां खरीदी गई हैं। उन्होंने दावा किया कि धन का शोधन करके इसका इस्तेमाल लोकसभा समेत अन्य चुनावों में किया गया। श्रीरामलु ने प्रेस वार्ता में दावा किया, घोटालेबाजों ने वाल्मीकि निगम के पैसे को लेम्बोर्गिनी कार खरीदी, हवाला के जरिए पैसे को इधर-उधर कर चुकाया है। पूर्व मंत्री नरसिम्हा नायक (राज गौड़ा) ने आरोप लगाया कि घोटाले में राज्य सरकार ने संदिग्ध भूमिका निभाई। नायक ने बताया, हम सब जानते हैं कि वित्त सचिव की मंजूरी के बिना तीन करोड़ रुपये से ज्यादा धन स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक ही

दिन में 50 करोड़ रुपये के स्थानांतरित कर दिए गए। आश्चर्य की बात है कि सरकार में किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। भाजपा नेता के अनुसार, यह पैसा 16 व्यापारियों के खातों में स्थानांतरित किया गया। स्थानांतरित की गई रकम 4.12 करोड़ से 5.98 करोड़ रुपये के बीच थी। दोनों भाजपा नेताओं ने कांग्रेस विधायक बी. नागेन्द्र की गिरफ्तारी की मांग की। नागेन्द्र ने घोटाला सामने आने के बाद जनजाति कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। कथित घोटाला तब सामने आया जब अनुसूचित जनजाति विकास निगम के लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन पी ने 26 मई को आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें आरोप लगाया गया कि निगम से 187 करोड़ रुपये की राशि अवैध रूप से स्थानांतरित की गई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इसमें कुछ आईटी कंपनियों और हैदराबाद स्थित सहकारी बैंक के विभिन्न खातों में अवैध रूप से 88.62 करोड़ रुपये जमा करना भी शामिल है।



भजनलाल का ऐतिहासिक बजट के लिए युवाओं ने जताया आभार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का युवाओं ने राज्य के परिवर्तित बजट 2024-25 में उनके लिए की गई ऐतिहासिक घोषणाओं पर आभार जताया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में युवाओं ने मुख्यमंत्री आवास पहुंच कर इसके लिए शर्मा का आभार प्रकट किया। आभार सभा में शर्मा ने कहा कि युवा देश के स्वर्णिम

भविष्य का आधार हैं। युवाओं की ऊर्जा तथा उत्साह से राजस्थान प्रगति की एक नई इबारत लिखेगा। हमारी सरकार युवाओं के सपनों तथा उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रति पल तथा प्रति क्षण काम कर रही है। शर्मा ने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए इस वर्ष में एक लाख नौकरियों की घोषणा की गई है। राज्य सरकार सार्वजनिक, निजी तथा व्यावसायिक सहित सभी क्षेत्रों में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उस प्रतिभा को सामने लाने की। सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज तथा 'खेलो राजस्थान यूथ गेम्स' जैसी घोषणाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को सामने लाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया गया था और पेपरलीक जैसे

मामलों से युवाओं को बड़ा आघात पहुंचा था। उन्होंने कहा कि वे युवाओं का दर्द समझते हैं तथा इन प्रकरणों में कड़ी कार्रवाई करते हुए किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर युवाओं को बड़ी संख्या में नियोक्ति पत्र प्रदान किए गए थे। इससे न केवल युवा बल्कि उनके परिवारजनों को भी सपना साकार हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शीघ्र ही राजस्थान

इनवेस्टमेंट समिट का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश एवं विदेशों से बड़े-बड़े उद्योगपति भाग लेंगे। समिट के माध्यम से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नवीन अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने युवाओं को आश्चर्य किया कि आगामी समय में हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से मिलकर संवाद भी किया। कार्यक्रम में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे।

उदयपुर ग्रामीण में मटुन माइन्स को फिर से शुरू करने का मामला न्यायालय में विचाराधीन : खींसर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com
जयपुर। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में हिंदुस्तान जिंक की इकाई मटुन माइन्स को पुनः शुरू करने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। खींसर ने बताया कि प्रश्नकाल के

दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्न का खान मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन में प्रकरण की शीघ्र सुनवाई के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मटुन माइन्स में खनिज रॉक फॉस्फेट के स्वीकृत खनन पट्टे की अवधि 03 मई, 2020 को समाप्त हो जाने के कारण खनन कार्य बंद है। हिंदुस्तान जिंक को 1970 में बीस साल के लिए लीज आवंटित की गई थी, जिसे दो बार दस-दस साल के

लिए बढ़ाया गया था। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा 2015 में लागू खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम-2015 के तहत केवल कैप्टिव माइनिंग होने पर ही लाइसेंस देने के प्रावधान के चलते लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हुआ। खनन कार्य पुनः शुरू करने का मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी अंतिम बार सुनवाई अक्टूबर, 2023 में हुई थी। इससे पहले विधायक फूल सिंह

मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खींसर ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में निकट ग्राम मटुन तहसील गिरवा (वर्तमान में कुराबड़) में खनिज रॉक फॉस्फेट के स्वीकृत रहे खनन पट्टे की अवधि 03 मई, 2020 को समाप्त हो जाने के कारण खनन कार्य बंद है। इस संबंध में कम्पनी द्वारा केन्द्रीय खान मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत रिचियोज प्रार्थना पत्र वर्तमान में विचाराधीन है।

स्वर्णिम भविष्य का आधार युवा, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना हमारा लक्ष्य : मुख्यमंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com
जयपुर। राजस्थान में महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों को लेकर बृहस्पतिवार को विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। सरकार ने जहां कहा कि उसके छह महीने के कार्यकाल में महिला उत्पीड़न के मामलों में छह प्रतिशत की कमी आई है तो वहीं उनके जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने हंगामा व नारेबाजी की। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा के एक प्रश्न के जवाब में प्रभारी मंत्री गजेन्द्र सिंह खींसर ने बताया कि राज्य में एक जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक महिला उत्पीड़न के 20767

जालोर : कॉलेज छात्रा की सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बना एडिटेड अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

जालोर। जालोर जिले की कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने कॉलेज में अध्ययनरत एक छात्रा की सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर एडिटेड अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर मिलने के लिए दबाव बनाने के मामले में आरोपी जेसा राम चौधरी पुत्र लक्ष्मणा राम (22) निवासी रतनपुर थाना गुडामालानी जिला बाड़मेर को कर्नाटक से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया है। एसपी ज्ञान चन्द्र यादव ने बताया कि 11 जनवरी को कॉलेज में अध्ययनरत एक 19 वर्षीय युवती ने थाना कोतवाली में अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दी कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उसके नाम की फर्जी आईडी बनाई। उसके फोटो को एडिटेड कर अश्लील फोटो बना उसे मैसेज कर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर मिलने के लिए दबाव बना रहा है। रिपोर्ट पर आईटी एक्ट स्त्री अशिक्षा रूपण (प्रतिशोध) अधिनियम एवं आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। अज्ञात आरोपी की तलाश एवं गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल व सीओ गौतम जैन के सुपरविजन एवं एसएचओ जसवंत सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों से आरोपी के मोबाइल नंबर मिलने पर उसे ट्रेस आउट किया। आरोपी जेसा राम के कर्नाटक राज्य में होने से वहां एक पुलिस टीम भेज कर गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। आरोपी को दस्तयाब कर बुधवार को पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 को, अधीनस्थ न्यायालयों में 512 पीठ गठित

जयपुर। इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को होगा जिसके लिए अधीनस्थ न्यायालयों में 512 पीठों का गठन किया गया है। 'रालसा' के एक पदाधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) के सदस्य सचिव हरि ओम अक्षरी ने बताया कि इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर पीठ सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के साथ-साथ राज्य न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों और अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में किया जाएगा। अक्षरी ने कहा कि जन सामान्य

पत्नी की हत्या कर पति ने की आत्महत्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com
श्रीगंगानगर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भावरा थाना क्षेत्र के करणपुरा गांव में एक व्यक्ति ने पत्नी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली है। पुलिस के अनुसार यह घटना कल रात की है। इस संबंध में जहां पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, वहीं पति के भाई की ओर से दी गयी रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। मृतक दंपति के शव भावरा के सरकारी अस्पताल में सुरक्षित रखे गये हैं। पुलिस के अनुसार कल देर शाम को सूचना मिली कि करणपुरा में रघुवीर जाट (35) ने पत्नी राजबाला (32) की किसी तेज धार वाले हथियार से सिर पर वार करके हत्या कर दी। इसके बाद उसने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। घटना में राजबाला की मौके पर ही मृत्यु हो गयी, जबकि रघुवीर को भावरा के सरकारी अस्पताल में ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। राजबाला के भाई अनिल जाट (22) निवासी भरोखा थाना सदर सिरसा (हरियाणा) की रिपोर्ट के आधार पर रघुवीर के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।



मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत अरण्य भवन में पौधारोपण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com
जयपुर। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में जयपुर स्थित अरण्य भवन में गुरुवार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी व अन्य अधिकारियों ने पौधे लगाए। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) अरिजीत बनर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में इस मानसून में 7 करोड़ पौधों का वितरण एवं रोपण

के साथसाथ 20 नगर वन एवं 33 लयकुश वाटिका सहित 80 हजार हेक्टेयर में पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके तहत निरन्तर पौधारोपण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वन विभाग की पौधशालाओं से एक जुलाई से अब तक लगभग 80 लाख पौधे वितरित किये जा चुके हैं। बनर्जी ने कहा कि पौधे लगाने की पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र का विस्तार करना है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को

स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके और प्रदेश हराभरा हो सके। उन्होंने बताया कि हरियाली का सर्जन हर घर पौधारोपण के तहत प्रदेश नागरिक को एक पौधा मां के नाम लगाकर उसकी सुरक्षा करनी चाहिए ताकि हमारा प्रदेश हरियाला राजस्थान व समूह राजस्थान की संकल्पना साकार हो सके। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन कुमार उपाध्याय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन सुशिक्षा मेहरा एवं अरण्य भवन

तथा जयपुर मुख्यालय स्थित अन्य उच्च अधिकारीगण, राजस्थान वन सेवा के अधिकारीगण एवं कार्यरत अन्य संघों के अधिकारीगण एवं कामियों ने भी पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेकर पौधे लगाए। इस कार्यक्रम में वन विभाग के मुख्यालय स्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने का संकल्प लिया, साथ ही पौधारोपण कर अपनी भागीदारी निभाई।

बच्चों को बेचने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई कर रही सरकार : खींसर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com
जयपुर। राजस्थान के आदिवासी इलाकों में गरीब दंपतियों द्वारा कथित तौर पर अपने बच्चों को बेचे जाने का मामला बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में उठा। सरकार ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए सदन को बताया कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है लेकिन इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। चिकित्सा एवं

स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींसर ने विधानसभा में कहा कि माता-पिता द्वारा अपने ही बच्चों को बेचे जाने की घटनाएं बेहद दुःखद हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है लेकिन इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। मंत्री ने कहा कि समाज के लोग जब मिलकर काम करेंगे तभी इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी रूप से लगाम लगाई जा सकेगी। बूंदी से कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया और

जानना चाहा कि सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की? खींसर ने प्रश्न के जवाब में बताया कि इस संबंध में फलासिया और बाघपुरा थाने में कुल सात मुकदमे दर्ज किये गये हैं, जिनमें से छह मामले वर्ष 2023 में और एक मामला 2024 में दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को 'अलर्ट' कर दिया है चिकित्सा मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए काउंसिलिंग किये जाने और गैर सरकारी संगठनों की भी आवश्यकता है।

महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर विधानसभा में हंगामा

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मंत्री सदन को गुमराह न करें क्योंकि अप्रैल 2024 में 2861 मामले दर्ज हुए जबकि मई में 4088 मामले दर्ज हुए। उन्होंने कहा, एक महीने में 43 प्रतिशत के आसपास की वृद्धि हुई है... आप छह प्रतिशत की कमी कहां से बता रहे हैं?

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com
जयपुर। राजस्थान में महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों को लेकर बृहस्पतिवार को विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। सरकार ने जहां कहा कि उसके छह महीने के कार्यकाल में महिला उत्पीड़न के मामलों में छह प्रतिशत की कमी आई है तो वहीं उनके जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने हंगामा व नारेबाजी की। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा के एक प्रश्न के जवाब में प्रभारी मंत्री गजेन्द्र सिंह खींसर ने बताया कि राज्य में एक जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक महिला उत्पीड़न के 20767

प्रकरण दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि गत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के छह महीनों से तुलना की जाए तो ऐसे मामलों में छह प्रतिशत की कमी आयी है। मंत्री ने कहा, 2022 से 2024 तक जनसंख्या तो बढ़ी है लेकिन ऐसे मामले इस दौरान छह प्रतिशत कम हुए हैं। महिला उत्पीड़न के मामलों में छह प्रतिशत की कमी आई है तो वहीं उनके जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने हंगामा व नारेबाजी की। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा के एक प्रश्न के जवाब में प्रभारी मंत्री गजेन्द्र सिंह खींसर ने बताया कि राज्य में एक जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक महिला उत्पीड़न के 20767

हूए हंगामा शुरू कर दिया। विधायक इंदिरा ने डिंपल मीणा प्रकरण को भी उठाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मंत्री सदन को गुमराह न करें क्योंकि अप्रैल 2024 में 2861 मामले दर्ज हुए जबकि मई में 4088 मामले दर्ज हुए। उन्होंने कहा, एक महीने में 43 प्रतिशत के आसपास की वृद्धि हुई है... आप छह प्रतिशत की कमी कहां से बता रहे हैं? मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायक सीटों से उठकर नारेबाजी करने लगे और अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए। इसको लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष में काफी देर तक बहस होती रही। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंगला प्रश्न पुकार लिया।

विधानसभा में लगे मुर्दाबाद के नारे, विपक्ष ने मदन दिलावर से मांगा इस्तीफा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र में आदिवासियों के डीएन का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने शिक्षामंत्री मदन दिलावर से माफी मांगने की माग की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जब तक मदन दिलावर अपने बयान से माफी नहीं मांगते, तब तक विपक्ष उनका जवाब नहीं सुनेगा। इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुर्दाबाद के नारे लगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम

जूली ने कहा कि मदन दिलावर पहले माफी मांगे, इसके बाद विपक्ष मंत्री का जवाब सुनेगा। बता दें भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोट ने एक बयान दिया था। राजकुमार रोट बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद हैं। राजकुमार रोट ने कहा था कि मैं हिंदू नहीं हूँ और आदिवासी का धर्म हिंदू नहीं है, इसके जवाब में मदन दिलावर ने कहा था कि देश को तोड़ने की गतिविधियां शुरू करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासियों को अपने आपको हिंदू नहीं होने के सवाल पर

मदन दिलावर ने कहा कि यह तो पूर्वजों से पता चल जाएगा। वंशवली लिखने वालों से पूछ लेंगे, उनके डीएनए की भी जांच करवा लेंगे। विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही में विधायक मनीष यादव ने सवाल पूछा, क्या महिला और बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक वेतन और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने के आदेशों की गतिविधियां शुरू करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासियों को अपने आपको हिंदू नहीं होने के सवाल पर



बंद व खनन कार्य पूरा हो चुकी खान क्षेत्रों में त्यापक प्लांटेशन कराए : कलाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com
जयपुर। निदेशक खान एवं भूविज्ञान भगवती प्रसाद कलाल ने माइनर मिनरल प्लांट्स के डेलिनिवेशन के लिए प्राथमिकता से खनिज क्षेत्र चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रदेश की निरस्त माइंस, राज्य सरकार को सरेण्डर की गई माइंस, लीज अवधि समाप्त हो चुकी माइंस और अन्य खनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर डेलिनिवेशन के काम में तेजी लाई जाए। खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों से बुधवार और गुरुवार को वीसी के माध्यम से रुबर होते हुए कलाल ने कहा कि अवैध खनन

प्रभावित क्षेत्रों और गेप एरिया में डेलिनिवेशन के काम को प्राथमिकता दी जाए ताकि ऐसे खनिज क्षेत्रों के प्लांट तैयार कर ऑक्शन किया जा सके। निदेशक माइंस कलाल ने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जिनके पास खान विभाग भी है अवैध खनन गतिविधियों को लेकर गंभीर हैं। मुख्यसचिव सुधांशु पंत व खान सचिव श्रीमती आनन्दी विभागीय अधिकारियों के साथ ही जिला कलक्टरों से सन्मन्थ्य बनाते हुए अभियान चलाकर कार्रवाई व उसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं। कलाल ने कहा कि विभाग की

जियोलोजी विंग को प्रतिमाह माइनर मिनरल के ऑक्शन के लिए 1173 हेक्टेयर क्षेत्रफल के प्लांट और मिनरलों की खोज के लिए प्रतिमाह 970 मीटर ड्रिलिंग के लक्ष्य दिए गए हैं। उन्होंने सभी 19 अधीक्षण भूविज्ञानी और विपक्ष भूविज्ञानी कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि माइनिंग विंग व जियोलोजी विंग में परस्पर सन्मन्थ्य सहयोग से ऑक्शन के लक्ष्यनुसार प्लांट तैयार किये जाएं। खेतक में ई-फाइलिंग, ई-डॉक, ई-फाइलिंग निष्पादन की चर्चा करते हुए निरन्तरता समय को न्यूनतम स्तर पर लाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। परिेश पॉटल में 31 जुलाई के पहले पहले फार्म 2 अपलोड करने के निर्देश दिए।

सुविचार

जिंदगी ने सवाल बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले, हम तो आज भी वही है जो कल थे, बस लोगों ने अपने जज्बात बदल डाले।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

टेलीकॉम: विविधता को मजबूत रखें

निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अपनी सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने के बाद आम ग्राहक की जेब पर काफी असर पड़ेगा। आज हर परिवार में दो से ज्यादा मोबाइल फोन होना आम बात है। अगर उन सबमें निजी कंपनियों के सिम कार्ड हैं तो साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि वाले ग्राहकों के लिए रिचार्ज करवाना मुश्किल होगा। पढ़ाई से लेकर खरीदारी और पानी, बिजली, गैस आदि के बिल जमा कराने तक, सब में इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। पिछले एक दशक से भी कम समय में भारत ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में जो कीर्तिमान रचे हैं, उनमें निजी टेलीकॉम कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि 21वीं सदी के आगाज के साथ भारत के टेलीकॉम बाजार में जो उछाल आया, उसका श्रेय बीएसएनएल को देना होगा। अपने 'अच्छे दिनों' में इसने सरकार के खजाने में बड़ा योगदान दिया, लेकिन उसके बाद बढ़ता घाटा एक बड़ी चुनौती बन गया। टेलीकॉम कंपनियों के बीच स्पर्धा प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ताकि आम ग्राहकों को उनके बजट के अनुसार बेहतर सुविधाएं मिलें। जब हम पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं तो उस लक्ष्य में भारत ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में जो कीर्तिमान रचे हैं, उनमें निजी टेलीकॉम कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि 21वीं सदी के आगाज के साथ भारत के टेलीकॉम बाजार में जो उछाल आया, उसका श्रेय बीएसएनएल को देना होगा। अपने 'अच्छे दिनों' में इसने सरकार के खजाने में बड़ा योगदान दिया, लेकिन उसके बाद बढ़ता घाटा एक बड़ी चुनौती बन गया। टेलीकॉम कंपनियों के बीच स्पर्धा प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ताकि आम ग्राहकों को उनके बजट के अनुसार बेहतर सुविधाएं मिलें। जब हम पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं तो उस लक्ष्य में भारत ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में जो कीर्तिमान रचे हैं, उनमें निजी टेलीकॉम कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अगर पिछले दो दशकों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि यह अवधि टेलीकॉम बाजार के लिए कई उपलब्धियों के बावजूद उथल-पुथल भरी रही है। इस दौरान कोई शून्य से शिखर तक पहुंचा, तो कोई अर्थ से फर्श पर आ गया। जहां कभी ग्राहकों की लंबी कतारें लगा करती थीं, वहां की रोक गायब हो गई। यह रिकॉर्ड बताता है कि जरूरी नहीं कि जो कंपनी आज बुलंदियों पर है, वह आगे भी अपनी बढ़त और मुनाफा बरकरार रख पाए। ऐसे में समय के साथ तकनीकी बदलाव करते हुए सुधारों का रास्ता अपनाया अनिवार्य है। आज काफी लोग बीएसएनएल में सिम पोर्ट करवा रहे हैं तो उसे चाहिए कि वह अतीत के अनुभवों से सीखते हुए भविष्य की संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करे। बीएसएनएल के पास इस क्षेत्र का समृद्ध अनुभव है, दूर-दराज के इलाकों में नेटवर्क है। अगर वह कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सुधारों पर जोर दे तो कमाल कर सकता है। आज जिन लोगों के मन में बीएसएनएल को लेकर अचानक 'लगाव' पैदा हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह निजी कंपनियों द्वारा शुल्क में बढ़ोतरी करना है। अगर सोशल मीडिया पर पुरानी पोस्ट्स में बीएसएनएल के ग्राहकों की टिप्पणियां पढ़ें तो उनमें ऐसी कई समस्याओं का जिक्र पाएंगे, जिनका अब तुरंत समाधान करना जरूरी है। ग्राहक के लिए शुल्क एक वजह हो सकती है, लेकिन उसके साथ नेटवर्क और संतुष्टि जैसे बिंदु भी बहुत मायने रखते हैं। अगर कोई ग्राहक मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि रफ्तार अच्छी हो। अगर बीच-बीच में व्यवधान आएगा तो एक समय बाद ग्राहक का मोर्चाभंग हो जाएगा। बीएसएनएल को नए-नए ऑफर लाकर अपना विस्तार करना चाहिए। उसके साथ कार्यशैली में फुर्ती लानी चाहिए। आज का युवा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वह हाथ में प्रार्थनापत्र लेकर दफ्तरों के चक्कर लगाए। उस पर पढ़ाई का इतना दबाव है कि एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक दौड़ लगाने के लिए न तो समय है और न ही इतना धैर्य है! वह जल्द नतीजे चाहता है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक को अपनाया जरूरी है। सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करनी होगी। बाजार में मजबूती से खड़े होने के लिए ग्राहक तक पहुंचने की पहल करते हुए उचित शुल्क के साथ मांग को पूरा करना होगा। बीएसएनएल के पास अनुभव खूब है, अब उत्साह के साथ नई उड़ान के लिए तैयारी करनी चाहिए।

ट्वीटर टॉक

आज जनपद बलरामपुर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के निरीक्षण के बाद यहां के राहत शिविर में आपदा से प्रभावित लोगों से संवाद किया। इस अवसर पर प्रभावितों को सहायता राशि के चेक और राहत सामग्रियां भी वितरित की गईं।

-योगी आदित्यनाथ

राजसमंद के चारभुजा थाना सर्किल में हुए भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मृत्यु का दुःख समाचार प्राप्त हुआ। प्रभु श्रीराम जी से दिवंगत आत्माओं को अपने शीघ्रगम में स्थान एवं शोक संतप्त परिवारों को इस दुःख की घड़ी में संबल प्रदान की प्रार्थना करती हूँ।

-दीया कुमारी

पर्यटन और संस्कृति के सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से राजस्थान सरकार का विजन शानदार है। नई पर्यटन नीति से रोजगार-विकास की नई संभावनाएँ निर्मित होंगी। इस दिशा में पर्यटन विकास बोर्ड और राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन बोर्ड क्रांतिकारी सिद्ध होंगे।

-गजेन्द्र सिंह शेखावत

प्रेरक प्रसंग

खालीपन में नकारात्मकता

एक बार महान कवि विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन गांव में रहने गये। कुछ शरारती किस्म के ग्रामीण युवक आदतन उनके कुदरत के प्रति प्रेम तथा लगाव पर टिप्पणी करने लगे। कुछ देर उनको खामोशी से सुनने के बाद वर्ड्सवर्थ ने कहा कि आप मेरा उपहास उड़ाने से पहले यह बता दीजिए कि आप अपने खेतों की फसल, अपने मवेशी तथा मौसम के बारे में क्या जानते हैं। युवक सोच में पड़ गये। कुछ बोलते नहीं बना। अरे, कहिये न, आप क्या कहते हैं। वह कुछ जानते तो कहेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि इसी प्रकृति का नियम है यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो कुदरत उसे घास-फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से अगर दिमाग में सकारात्मक विचार न रखे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं।



समय की मांग है तार्किक पाठ्यक्रम

प्रियंका सोरभ

एनसीईआरटी कक्षा छह से दस तक की इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव कर रहा है। एक मजबूत शिक्षा प्रणाली में शिक्षण सामग्री का संशोधन पाठ्यक्रम के लिए समान होना चाहिए। लेकिन भारत में स्कूली पाठ्यक्रम हमेशा नवीनतम शोध के साथ तालमेल बनाए रखते हैं। पक्षपातपूर्ण या संकीर्ण दृष्टिकोण से बचने के लिए स्वतंत्रता के बाद से, हमारी स्कूली पाठ्यपुस्तकें अक्षर कला, साहित्य, दर्शन, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास में भारत की प्रगति को मान्यता देने से बचती हैं। पहले की पाठ्यपुस्तकें भारतीय इतिहास के बारे में एक ऐसा दृष्टिकोण बनाती हैं जो विश्व की सभ्यता पर भारत के गहन प्रभाव को दबा देती हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारी राष्ट्रीय पहचान और ऐतिहासिक कथा के बारे में एक विषम धारणा बनती है। स्कूली विद्यार्थियों को कम उम्र में ऐतिहासिक घटनाओं और संघर्षों की आक्रामकता के संघर्ष में लाना उन्हें संकट में डाल सकता है। स्कूली पाठ्यक्रम में शिक्षा के अनुचित चरणों में ऐतिहासिक संघर्षों का परिचय, बच्चों के दिमाग में व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ की कमी की धारणा को अमर कर सकता है। एक संतुलित कथा बच्चों के दिमाग में दुश्मनी और पूर्वाग्रह पैदा करने के जोखिम को कम करती है। एकतरफा ऐतिहासिक तथ्य स्कूली बच्चों के बीच सामाजिक सामंजस्य और आपसी सम्मान में बाधा डालेंगे। सार्थक पाठ्यपुस्तक संशोधनों का विरोध एक पुरानी संकीर्ण वैचारिक विचार प्रक्रिया को दर्शाता है, जो भविष्य में ऐतिहासिक शिकायतों और शत्रुता को शाश्वत बनाता है। एक संतुलित, विश्वसनीय और भरोसेमंद ऐतिहासिक कथा, संघर्ष समाधान और आपसी सम्मान के सकारात्मक उदाहरणों को रेखांकित करती है। यह छात्रों को अपने जीवन में सकारात्मक उदाहरणों और सिद्धांतों को लागू करने के लिए



प्रेरित करती है। स्कूली छात्रों को एक संतुलित इतिहास पढ़ाना जो संघर्ष-आधारित कथाओं को कम करता है, उन्हें भारत की विरासत के बारे में बेहतर जानकारी के साथ जिम्मेदार और सहानुभूतिपूर्ण नागरिक बनने में सक्षम बनाता है। ऐसी पाठ्य पुस्तकें बच्चों में सज्जानात्मक और भावनात्मक आधार बनाती हैं, जो भविष्य के आलोचनात्मक चिन्तन के लिए आवश्यक हैं। संतुलित कथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूली पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने का कोई भी प्रयास अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। छात्रों को ऐसी संतुलित पाठ्यपुस्तकों से जो आधार मिलता है, वह उन्हें बाद के वर्षों में एक गहरी ऐतिहासिक समझ बनाने में मदद करेगा। स्कूली पाठ्यपुस्तकों को छात्रों की उभरती जरूरतों को पूरा करने में उत्तरदायी होने के लिए बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। पाठ्य पुस्तकों में क्या पढ़ाया जाए और क्या न पढ़ाया जाए, इसकी चर्चा लगातार होती रही है, क्योंकि स्कूल की पाठ्यपुस्तकें ही वह माध्यम कथा, संघर्ष समाधान और आपसी सम्मान को बढ़ावा दे सकती हैं। विवाद तब होता है, जब एक विमर्श आपके लिए सुविधाजनक होता है और दूसरे वर्ग के लिए असुविधाजनक। वर्तमान में

इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में किए गए कुछ बदलावों से संबंधित विवाद को भी उसी संदर्भ में देखना चाहिए, जब एक वर्ग का सुविधाजनक दृष्टिकोण दूसरे वर्ग के विमर्श के अनुरूप नहीं होता है। देखा जाए तो इस प्रकार का विवाद पहली बार नहीं हुआ है। भारत के शैक्षणिक इतिहास में इस प्रकार के विवाद पहले भी होते रहे हैं। विश्व भर की शिक्षा व्यवस्थाएं अपने-अपने देश के पाठ्यक्रम को समझ और तार्किक दृष्टिकोण पर आधारित बनाना चाह रही हैं, वहीं हमारे देश में विवाद इस बात पर हो रहा है कि किस पक्ष का तथ्य सही है? यहां असुविधाजनक तथ्य को वृत्तान्त की सहायता से सदैव छुपाने का प्रयास रहता है। इतिहास को न केवल तथ्यों से समझा जा सकता है और न केवल वृत्तान्तों से। इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों का उचित मात्रा में समावेश हो, मगर हमारे देश में इतिहास लेखन की शैली में तथ्य और वृत्तान्त का विभाजन काफी बारीक है। इस विषय के पुनरावलोकन की आवश्यकता है। जहां पूरे विश्व की शैक्षणिक व्यवस्थाएं अपने स्वरूप को बदल रही हैं और छात्रों को तथ्यों से भरने के बजाय उन्हें इतिहास आधारित दृष्टिकोण से युक्त करने पर जोर दे रही हैं, जिससे छात्रों में इतिहास के प्रति एक वस्तुनिष्ठ

दृष्टिकोण विकसित हो सके। आज के तकनीकी दौर में इतिहास बोध होने पर छात्र स्वयं ही ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल कर सकता है। किसी देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि वह अपने छात्रों को तथ्य आधारित, वस्तुनिष्ठ पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराए, क्योंकि यही छात्र भविष्य के विमर्श को न केवल आगे बढ़ाते हैं, अपितु नए विमर्श की शुरुआत भी करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इतिहास में एकपक्षीय दृष्टिकोण से आगे बढ़कर चिंतन और तार्किक पाठ्यक्रम का विकास किया जाए। एनसीईआरटी से अपेक्षा है कि वह वर्तमान विवाद से अप्रभावित रहते हुए छात्रों के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के विकास से संबंधित पाठ्यक्रम का विकास करेगी, न कि तथ्यों के चयन में छात्रों को उलझाएगी। पाठ्य पुस्तकें किसी देश की सरकार द्वारा विद्या गया आधिकारिक कथन होती हैं। इस रूप में ये वैचारिक या सैद्धांतिक परिचयोजना होती हैं। इतिहास और राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का पुनरीक्षण वैसे भी अधिक संवेदनशील होता है। विषय समकालीन प्रासंगिकता के मुद्दों पर विचार करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं।

उन्हें सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को इतिहास के पलके पर तोलकर, इतिहास और वर्तमान के बीच तार्किक सामंजस्य बनाया सिखाते हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी हमारे देश में विवाद इस बात पर हो रहा है कि किस पक्ष का तथ्य सही है? यहां असुविधाजनक तथ्य को वृत्तान्त की सहायता से सदैव छुपाने का प्रयास रहता है। इतिहास को न केवल तथ्यों से समझा जा सकता है और न केवल वृत्तान्तों से। इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों का उचित मात्रा में समावेश हो, मगर हमारे देश में इतिहास लेखन की शैली में तथ्य और वृत्तान्त का विभाजन काफी बारीक है। इस विषय के पुनरावलोकन की आवश्यकता है। जहां पूरे विश्व की शैक्षणिक व्यवस्थाएं अपने स्वरूप को बदल रही हैं और छात्रों को तथ्यों से भरने के बजाय उन्हें इतिहास आधारित दृष्टिकोण से युक्त करने पर जोर दे रही हैं, जिससे छात्रों में इतिहास के प्रति एक वस्तुनिष्ठ

नजरिया



बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि अमी भी हमारे देश में आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं। बहुत सारी छोटी-छोटी नौसमी बीमारियों तक का इलाज, खासकर दूरदराज के अनेक ग्रामीण इलाकों में आज भी सहज उपलब्ध नहीं है और जहां प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच गई हैं, वहां भी शायद ही इस तरह की स्वास्थ्य-समस्या के इलाज की समुचित व्यवस्था होगी। इसलिए हमारे सामने जो चुनौती है, वह बहुत ज्यादा बड़ी है। इसी के साथ-साथ यह भी बहुत जरूरी है कि इस समस्या से बचाव के तरीकों का देश में पर्याप्त प्रचार-प्रसार हो। यह बहुत कठिन काम नहीं है।

बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल स्वास्थ्य के लिए घातक

ललित गर्ग

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भारत का अनेक खतरों से लड़ना-बढ़ना होना चिन्ता में डाल रहा है। बढ़ती शारीरिक निष्क्रियता के साथ मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप जैसे रोग दबे पांव इंसानों को घेर कर बड़ी चुनौतियां बन रहे हैं, जिन्हें बड़े खतरों के रूप में देखा जाना चाहिए। इन्होंने बढ़ते खतरों के बीच देश में कोलेस्ट्रॉल एक नई स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभरा है। कार्डियोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया की 22 सदस्यीय समिति ने अब अधिक कोलेस्ट्रॉल की वजह से होने वाले डिस्लिपिडेमिया को लेकर जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, वे इसी मायने में महत्वपूर्ण एवं स्वास्थ्य के मोर्चे पर गंभीर हैं। शरीर का यह ऐसा विकार है, जिसका पता अक्सर खुद उसके शिकार को भी नहीं चल पाता, क्योंकि अक्सर इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते। नतीजा यह होता है कि वह धीरे-धीरे हृदय रोग और गंभीर स्थितियों में हृदयाघात जैसी समस्याओं की ओर बढ़ता जाता है। बहरहाल, इस संगठन ने भारत के बारे में जो आंकड़े दिए हैं, वे डराने वाले हैं। देश की 81 फीसदी आबादी में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सुरक्षित सीमा से काफी ज्यादा मिला है, यानी चुपचाप होने वाले इस शारीरिक विकार का खतरा देश की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से पर मंडरा रहा है। कोलेस्ट्रॉल की पहचान के लिए लोगों को लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। शरीर में लिपिड का लेवल कितना हो इसके लिए भारत की अपनी पहली गाइडलाइन बनाई गई है। कोलेस्ट्रॉल का बेहतर ढंग से इलाज दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना बेहद खतरनाक होता है। इसके कई तरह की गंभीर शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। आज जितनी भी नई-नई बीमारियां उभर रही हैं, उसका कारण असंतुलित एवं सुविधाकारी जीवनशैली है। डिस्लिपिडेमिया को जीवन शैली से जुड़ी समस्या माना जाता है। कहा जाता है कि

इस समस्या के मूल में आर्थिक समृद्धि के कारण लोगों की खान-पान, नशा एवं उन्मुक्त जीवनशैली है। देर रात को सोना एवं सुबह देर से उठना, ना खाने का समय, ना शरीर को तपाने की कोई पद्धति। फास्ट-फूड के आधुनिक दौर में अब हमारे भोजन में ज्यादा शर्करा, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज्यादा वसा होने के कारण यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। निश्चित ही यह यह रोग अमीर लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन बड़ी समस्या यह है एक बड़ी आबादी इसकी गिरफ्त में आ गयी है। वह गरीब आबादी जो देश में आज मुफ्त अनाज पर निर्भर है। इसलिये बहुसंख्यक लोगों में इस रोग के पनपने एवं शारीरिक समस्या के लिए सिर्फ हम जीवनशैली को दोषी नहीं ठहरा सकते। यही वजह है कि भारतीय स्थितियों में इस समस्या के प्रसार के अमी और गहन एवं गंभीर अध्ययन की जरूरत है। इस बढ़ते खतरे को समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो भारत बीमारों का देश बन जायेगा। भारत में डिस्लिपिडेमिया की बीमारी तेजी से फैल रही है, जो एक साइलेंट किलर की तरह है। इस बीमारी के लक्षण तो नजर नहीं आते लेकिन यह धीरे-धीरे शरीर को खराब करता है। यह अटैक और हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियों का जोखिम बढ़ा देती है। निश्चित ही कोलेस्ट्रॉल को लेकर जो खबर आई है, वह बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि, इसके पीछे की जो पहल है, उसकी तारीफ तो की ही जानी चाहिए। पहली बार देश में कोलेस्ट्रॉल को लेकर दिशा-निर्देश जारी हो चुके हैं।

अभी तक जब देश के डॉक्टर मरीजों के कोलेस्ट्रॉल या सरल भाषा में कहें, तो शरीर में जमा हो गई चर्बी का इलाज करते थे या लोगों को लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने की हिदायत देते थे, तो वे यह काम यूरोपियन सोसायटी ऑफ कार्डियोलॉजी के दिशा-निर्देशों के तहत कर रहे हैं। हार्ट अटैक को लेकर अक्सर वे कहा जाता रहा है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, तंबाकू सेवन, मद्यपान आदि के कारण हार्ट अटैक होते हैं, लेकिन इसके विपरीत भारत में हार्ट अटैक के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो

चीज देखी गई है, वह है डिस्लिपिडेमिया यानि लिपिड प्रोफाइल जो भारत में 80 फीसदी लोगों में नॉर्मल नहीं है और न ही लोगों को इसकी जानकारी ही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत में पिछले 10 सालों में दिल का रोग बढ़ता गया है। इसका बड़ा कारण खानपान, खराब एवं असंतुलित हुई जीवनशैली, दैनिक शारीरिक गतिविधि में आई कमी सहित दूसरे कारण हैं।

इस बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि अमी भी हमारे देश में आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं। बहुत सारी छोटी-छोटी नौसमी बीमारियों तक का इलाज, खासकर दूरदराज के अनेक ग्रामीण इलाकों में आज भी सहज उपलब्ध नहीं है और जहां प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच गई हैं, वहां भी शायद ही इस तरह की स्वास्थ्य-समस्या के इलाज की समुचित व्यवस्था होगी। इसलिए हमारे सामने जो चुनौती है, वह बहुत ज्यादा बड़ी है। इसी के साथ-साथ यह भी बहुत जरूरी है कि इस समस्या से बचाव के तरीकों का देश में पर्याप्त प्रचार-प्रसार हो। यह बहुत कठिन काम नहीं है। उदाहरण की हमारे पास है। सही तरीके से प्रचार के कारण ही कोविड के दौर में बहुत बड़ी आबादी ने मारक पहनने, सार्वजनिक दूरी बनाने, खानपान को संतुलित करने के उपक्रम शुरू कर दिए थे।

कोलेस्ट्रॉल के इलाज को सर्वसुलभ बनाने के रास्ते भी हमें खोजने होंगे। हमारे देश की आधी आबादी शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं है। भारत की जनता शारीरिक रूप से सक्रियता के मामले में दुनिया में 12वें नंबर पर है। द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल के अनुसार हमारे देश में 57 फीसदी महिलाएं शारीरिक रूप से निष्क्रिय हैं। वहीं, इस सूची में पुरुष तकरीबन 42 फीसदी हैं। दुनिया की बड़ी चिन्ताओं में स्वास्थ्य प्रमुख है। सभी देशों में स्वास्थ्य की स्थिति सोचनीय एवं परेशान करने वाली है। वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिक क्रांति, बढ़ती आबादी, शहरीकरण तथा आधुनिक जीवन के तनावपूर्ण वातावरण के

कारण शारीरिक एवं मानसिक रोगों में भारी वृद्धि हुई है। यह किसी एक राष्ट्र के लिये नहीं, समूची दुनिया के लिये चिन्ता का विषय है। अस्वास्थ्य वर्तमान युग की एक व्यापक समस्या है। चारों ओर बीमारियों का दुर्भेद घेरा है। निरन्तर बढ़ती हुई बीमारियों को रोकने के लिये नई-नई चिकित्सा पद्धतियां असफल हो रही हैं। जैसे-जैसे विज्ञान रोग-प्रतिरोधक औषधियों का निर्माण करता है, वैसे-वैसे बीमारियां नये रूप, नये नाम और नये परिवेश में प्रस्तुत हो रही हैं। उच्चव्युत्पन्न देशों के मुताबिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ स्वास्थ्य खाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि कैसे दुनिया एक साथ आकर सभी को लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकती है।

भारत की चिकित्सा स्थितियां एवं सेवाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जहां सुधर रही हैं, वहीं स्वास्थ्य-स्थितियां नई-नई चुनौतियां लेकर खड़ी हो जाती हैं। इसलिये चिकित्सा-स्थितियों के साथ-साथ स्वास्थ्य-स्थितियों में सुधार की तीव्रता से अपेक्षा है। भारत में स्वास्थ्य-क्रांति का शंखनाद हो, यह व्यक्तियों को स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करें, सरकारों को स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और संसाधनों में निवेश करने के लिए प्रेरित करें और स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में लगातार सुधार करने के लिए प्रेरित करें। बीमारियों पर नियंत्रण के लिये योग एवं साधना, संतुलित आहार एवं संयमित जीवनशैली को भी प्रोत्साहित किया जाये। जितनी भी मानसिक और कायिक बीमारियां या विकृतियां उत्पन्न होती हैं, वे इस बात की गवाह है कि किसी एक नए 'रोड क्रॉसिंग' पर खड़े 'ट्रेफिक पुलिस' के निर्देशों की अपेक्षा कर 'ओवर टेकिंग' की कोशिश की है। सारी दुनिया में बढ़ते हुए मनोरोग एवं हृदयरोग इसी आंतरिक अस्वस्थता का परिणाम हैं। अन्य असाध्य बीमारियों का कारण भी असंतुलित जीवनशैली है। इसलिये अच्छे स्वास्थ्य के लिये मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बरतना नितान्त अनिवार्य है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सुरक्षा परिषद, डब्ल्यूटीओ में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है ब्रिक्स : बिरला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रमुख विकासशील देशों का संगठन 'ब्रिक्स' वैश्विक शासन व्यवस्था को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 'ब्रिक्स संसदीय मंच' में

उन्होंने समावेशी और सतत विकास के ब्रिक्स के एजेंडा को आगे बढ़ाने में संसद और सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए यह भी कहा कि भारत इस दिशा में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है।

लोकसभा सचिवालय की ओर से नई दिल्ली में जारी विज्ञापित अनुसार, 'ब्रिक्स संसदीय मंच' में चार नए सदस्यों मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का स्वागत करते हुए बिरला ने नए सदस्यों को संगठन में निबाध रूप से शामिल किए जाने के लिए रूस



की अध्यक्षता की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष का कहना था, "विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला ब्रिक्स

वैश्विक शासन व्यवस्था को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने तथा वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन जैसे

अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने उभरते बाजारों और विकासशील देशों को एकजुट करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के साथ ही परस्पर सम्मान, समझ, समानता, एकजुटता, पारदर्शिता, समावेशिता और आम सहमति के सिद्धांतों के प्रति भारत की निष्ठा के बारे में भी बात की। उन्होंने भारत में हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव का उल्लेख किया और कहा कि लोक सभा चुनाव में लगभग 65 करोड़ मतदाताओं ने वोटिंग की जिसके पश्चात नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधान मंत्री पद

की शपथ ली। बिरला का कहना था, "यह मेरा सौभाग्य है कि देश के निर्वाचित सदन लोकसभा ने मुझे लगातार दूसरी बार स्पीकर पद पर निर्वाचित किया।"

ब्रिक्स के सदस्य देशों और अन्य बहुवैश्विक मंचों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देते हुए ओम बिरला ने कहा कि भारत 'यसुधैव कुटुम्बकम्' अर्थात् समस्त संसार एक परिवार है के सिद्धांत पर चलता है जो ब्रिक्स द्वारा अभिव्यक्त समानता, एकजुटता और परस्पर लाभकारी सहयोग की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।



ब्रिटिश भारतीय सांसदों ने 'भगवद् गीता', 'गुटका', 'बाइबिल' की शपथ ली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लंदन/भाषा। ब्रिटिश संसद के निचले सदन 'हाउस ऑफ कॉमन्स' के लिए नवनिर्वाचित भारतीय मूल के सांसद देश के प्रति वफादारी के प्रतीक के रूप में महाराजा के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ले रहे हैं। इसके लिए उन्होंने धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर शपथ ली।

शैलेश वारा द्वारा स्पीकर लिंडसे होयल को 'भगवद् गीता' की एक नई प्रति भेंट की गई। शैलेश वारा कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व सांसद हैं, जो पिछले सप्ताह के आम चुनाव में कैम्ब्रिजशर सीट से हार गए थे। मंगलवार को शपथ लेने वाले पहले

ब्रिटिश भारतीय सांसदों में ऋषि सुनक भी शामिल थे, जिन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री सुनक ने परम्परागत पाठ पढ़ा: मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं कानून के अनुसार महामहिम महाराजा चाल्सर्स, उनके उत्तराधिकारियों और आने वाली पीढ़ियों के प्रति वफादार रहूंगा और सभी निष्ठा रखूंगा। इसलिए ईश्वर मेरी मदद करें। पहली बार सांसद बने भारतीय मूल के कनिष्क नारायण ने अपनी शपथ के लिये 'गीता' को चुना। वह वेल ऑफ ग्लोबल सांसदों से लेबर पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। लीसेस्टर से चुनाव जीतने वाली भारतीय मूल की शिवानी राजा ने भी 'गीता' पर हाथ रखकर शपथ ली।



प्यार की तलाश में दो अफ्रीकी शेरों ने की सबसे लंबी तैराकी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। शेरानियों के प्यार की तलाश में दो शेरों ने दरियाई घोड़ों और मगरमच्छों से प्रभावित मानी जाने वाली अफ्रीकी नदी को 1.3 किलोमीटर तक तैरकर पार किया। इससे यह दृश्य साक्ष्य के साथ अफ्रीकी शेरों का सबसे लंबे समय तक तैरने का रिकॉर्ड बन गया। संबंधित दोनों शेर आपस में भाई बताए जाते हैं।

पत्रिका 'इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन' में प्रकाशित अध्ययन के लेखकों के अनुसार, शेरानियों ने इसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने और तैराकी से पहले के घंटों

में मादा प्रेम के लिए लड़ाई हारने के बाद दोनों शेरों ने खतरनाक यात्रा पर निकलने का निर्णय किया क्योंकि उन्हें नदी के दूसरी ओर शेरनी मिलने की संभावना थी। अध्ययन से जुड़े लोगों ने ज़ोन कैमरों की मदद से काज़िगा चैनल को पार करने से पहले युगुंडा में क्रीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क से गुजरते शेरों का वीडियो बनाया। मानव हस्तक्षेप और अवैध शिकार के कारण पेंथेरा प्रजाति के शेरों की आबादी केवल पांच वर्षों में लगभग आधी हो गई है। इन शेर भाइयों की जोड़ी में से एक कई प्राणदायक घटनाओं से बचने के लिए जाना जाता है। अध्ययनकर्ताओं ने इसे फेडरल नाम दिया और कहा कि यह एक स्थानीय नायक है।

यूरोप, एशिया और अमेरिका के बीच खाई को पाटने की दिशा में काम कर रहे हैं: ब्लिंकन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वॉशिंगटन/भाषा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन का प्रशासन यूरोप, एशिया और अमेरिका के बीच की खाई को कम करने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने बुधवार को यहां नाटो शिखर सम्मेलन से इतर यह बात कही।

इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका के हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझेदारों- ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह लगातार तीसरी बार है जब अमेरिका ने अपने हिंद प्रशांत भागीदारों को आमंत्रित किया है। ब्लिंकन ने कहा, "जब रूस ने आक्रामकता दिखाई और यूक्रेन पर आक्रमण किया जब जापान खड़ा हुआ, दक्षिण कोरिया खड़ा हुआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी आगे आए। यह एक प्रकार से इस बात की स्वीकार्यता है कि ये चुनौतियां जुड़ी हुई हैं और जब लोकतंत्र एकजुट होते हैं तो हम और मजबूत होते हैं, प्रभावशाली होते हैं फिर चाहे हम यूरोप में हों, एशिया में हों या फिर कहीं और।"

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के प्रति प्रतिबद्धता के साथ ही परस्पर सम्मान, समझ, समानता, एकजुटता, पारदर्शिता, समावेशिता और आम सहमति के सिद्धांतों के प्रति भारत की निष्ठा के बारे में भी बात की। उन्होंने भारत में हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव का उल्लेख किया और कहा कि लोक सभा चुनाव में लगभग 65 करोड़ मतदाताओं ने वोटिंग की जिसके पश्चात नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधान मंत्री पद की शपथ ली। बिरला का कहना था, "यह मेरा सौभाग्य है कि देश के निर्वाचित सदन लोकसभा ने मुझे लगातार दूसरी बार स्पीकर पद पर निर्वाचित किया।"

राजनीतिक स्थिरता व विकास के लिये है नेपाली कांग्रेस-यूएमएल गठबंधन : ओली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

काठमांडू/भाषा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल 'प्रचंड' को छोड़कर नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाने के अपनी पार्टी के फैसले का बचाव करते हुए सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष के पी शर्मा ओली ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और देश के विकास के लिए यह आवश्यक है।

सत्तारूढ़ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी ओली के नेतृत्व वाले सीपीएन-यूएमएल ने पिछले सप्ताह नेपाली कांग्रेस के साथ सत्ता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। माना जा रहा है कि प्रचंड शुक्रवार को विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएंगे।

नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और इसके 89 सदस्य हैं जबकि सीपीएन-यूएमएल के 78 सदस्य हैं। दोनों दलों के एक साथ आ जाने के बाद नये गठबंधन के पास 167 सदस्य हो गये हैं जो बहुमत के

लिये आवश्यक 138 सीट से कहीं अधिक है। प्रचंड की पार्टी के पास कुल 32 सीट हैं। प्रचंड के विश्वासमत हासिल नहीं कर पाने की सूत्र में ओली शनिवार को प्रधानमंत्री बन सकते हैं और रविवार को यह पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। पार्टी सचिवालय में बुधवार को ओली (72) ने कहा कि वो बड़े राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन 'देश के विकास और राजनीतिक स्थिरता को बनाये रखने के लिये आवश्यक था'।

सीपीएन-यूएमएल के आठ कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के बाद प्रचंड (69) ने घोषणा की थी कि वह त्यागपत्र नहीं देंगे बल्कि संसद में विश्वास मत का सामना करेंगे। नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल ने संसद के शेष तीन साल के कार्यकाल के लिए बारी-बारी से सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

'हीरामंडी' के अभिनेता ताहा शाह ने 'अपने आदर्श' टॉम क्रूज से की मुलाकात

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लंदन/भाषा। 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' के अभिनेता ताहा शाह बुधवार को सुपरस्टार टॉम क्रूज

से हाल ही में लंदन में मुलाकात की। ताहा शाह ने इंस्टाग्राम पर क्रूज के साथ एक तस्वीर और वीडियो साझा किया और टॉम क्रूज को 'अपना आदर्श' बताया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा "अभी अपने आदर्श टॉम क्रूज से मुलाकात की।" वीडियो में वह क्रूज के साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में क्रूज ने जब ताहा शाह को गले लगाया तो वह मुस्कुरा रहे थे। ताहा शाह ने नेटफ्लिक्स पर प्रसारित वेब सीरीज 'हीरामंडी' में ताजदार बल्क नामक एक युवा एवं विद्रोही नवाब की भूमिका निभाई थी जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया। इसका निर्देशन संजय लीला भंशाली ने किया था। क्रूज जल्द ही 'मिशन: इम्पॉसिबल - 8' में नजर आएंगे।

विदेशी ऑर्डर पूरा करने के लिए दिन-रात काम में जुटे कोलकाता के मूर्तिकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े पर्व दुर्गा पूजा में अभी लगभग तीन माह शेष हैं, लेकिन मूर्तिकारों का कैद करे जाने वाले उत्तरी कोलकाता के कुम्हारटोली इलाके में कारीगर विदेशी ऑर्डर को समय पर पूरा करने के लिए दिन-रात मूर्तियों को तैयार करने में जुटे हुए हैं।

विदेशों से पूजा आयोजकों के ऑर्डर को पूरा करने के लिए अलग-अलग आकार में देवी की मूर्तियों को सावधानीपूर्वक तैयार किया जा रहा है। इस वर्ष दुर्गा पूजा नौ से 13 अक्टूबर तक मनाया जाएगा।

प्रसिद्ध मूर्तिकार कोशिक घोष लंदन की दुर्गाोत्सव समिति के लिए आठ फुट से अधिक ऊंची फाइबरग्लास मूर्ति बनाने में जुटे हैं और इसके लिए वह दिन-रात काम कर रहे हैं।

घोष ने कहा, "इस साल कम से कम 36 मूर्तियां ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और सिंगापुर जैसे देशों में भेजी जाएंगी। इस खेप का आधा हिस्सा इसी माह समुद्र या हवाई मार्ग से भेजा जाएगा, जबकि बाकी अग्रस्त तक भेजा जाएगा।" उन्होंने कहा, "हम

हर मूर्ति में मां दुर्गा के 'साबेकी' (पारंपरिक) रूप को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, हम कुछ न कुछ खास करने की कोशिश करते हैं।

पूजा समितियों के लिए मूर्तियां बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि 11 मूर्तियां पहले ही अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड और दुबई जैसे देशों में भेजी जा चुकी हैं।

पाल ने कहा, "छह मूर्तियां अमेरिका भेजी गई हैं, जहां विभिन्न प्रांतों में रहने वाले बंगाली प्रवासी इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। इसी तरह जर्मनी और स्विट्जरलैंड में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोग भी दुर्गा पूजा के लिए उतने ही उत्साहित रहते हैं।"

मूर्तिकार मंदू पॉल ने बताया कि उनकी एक मूर्ति पहले ही अमेरिका के फ्लोरिडा भेज दी गई है, तथा उसी स्थान के लिए दो और मूर्तियां बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है।

पॉल ने कहा, "आने वाले हफ्तों में मूर्तियां जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भेजी जाएंगी।" उन्होंने बताया कि मां दुर्गा की छोटी प्रतिमाओं के इच्छुक आयोजकों के लिए दो 'एकचाला' प्रतिमाएं तैयार रखी हैं, जिनमें से प्रत्येक लगभग तीन फीट ऊंची है।

पॉल ने कहा, "एक मूर्ति की कीमत लगभग 15,000 रुपये है। ये मूर्तियां बंगाली संगठनों या मित्रों के समूहों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध हैं।" कारीगर मूर्तियों की बुकिंग प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन मंचों का भी उपयोग कर रहे हैं।



उदाहरण के लिए, लंदन की पूजा में एक 'एकचाला' मूर्ति होगी...। एक अन्य कारीगर भिंदू पाल विदेशों की 21

कृति सैनन ने अलीबाग में 'द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा' की परियोजना में खरीदी जमीन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन ने महाराष्ट्र के अलीबाग में रिएल्टी कंपनी 'द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा' की परियोजना में 2,000 वर्ग फुट जमीन खरीदी है।

'द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा' ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि अभिनेत्री कृति सैनन ने

उसके प्रीमियम प्रोजेक्ट 'सोल डे अलीबाग' में 2,000 वर्ग फुट जमीन खरीदी है। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन ने अपने पहले निवेश पर कहा, "खुद से जमीन खरीदना मेरे खुद के सशक्तीकरण की यात्रा रही। काफी समय से मेरी नजर अलीबाग पर थी।" हाल में अमिताभ बच्चन ने अलीबाग में इसी प्रोजेक्ट में 10,000 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदा है।



तेल टैंकर पोत 'एडवांटेज स्वीट' अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र की ओर बढ़ा, ईरान ने किया था जल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दुबई/एपी। ईरान द्वारा लगभग एक वर्ष पहले जब्त किया गया एक तेल टैंकर पोत बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। 'ट्रेकिंग डाटा' से यह जानकारी सामने आई है।

मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाला टैंकर 'एडवांटेज स्वीट' होर्मुज जलडमरूमध्य की ओर बढ़ गया है और इसी जलक्षेत्र में अप्रैल 2023 में ईरान की नौसेना ने इसे जब्त कर लिया था। ईरान ने हालांकि टैंकर के आगे बढ़ने की बात स्वीकार नहीं की। यह

घटनाक्रम तब सामने आया है जब ईरान की एक अवातल ने अमेरिका सरकार को आदेश दिया कि वह तेहरान पर वाशिंगटन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से दुर्लभ तत्वों का विकास से पीड़ित लोगों के लिए स्वीडन की एक कंपनी से विशेष पेट्रोल की आपूर्ति रूकने की वजह से 6.7 अरब डॉलर से अधिक का मुआवजा प्रदान करे।

ईरान के तेहरान स्थित अंतरराष्ट्रीय संबंध कानून न्यायालय के इस आदेश से पहले ईरान ने पिछले साल पश्चिम के साथ तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी उर्जा कंपनी शेवॉन कॉर्प के लिए कुवेती कच्चे तेल से संबंधित पांच करोड़ डॉलर का सामान जब्त कर लिया था।



सरकारी समाचार एजेंसी 'इरना' की खबर के अनुसार 6.7 अरब डॉलर के मुआवजे से संबंधित आदेश 300 वादियों की ओर से दायर मुकदमों में आया। खबर में कहा गया है कि प्रतिबंधों के कारण स्वीडन की कंपनी द्वारा विशेष पेट्रोल की आपूर्ति न किए जाने से 'एपिडमॉलिसिस बुलोसा' नामक दुर्लभ तत्व रोग से 20 मरीजों की मौत हो गई। यह आदेश तब आया है जब अमेरिकी न्यायाधीशों ने ऐसे फैसले दिये हैं जिनमें तेहरान से जुड़े हमलों और उसके द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों तथा उन्हें देशों के बीच बातचीत में मोहरे के रूप में इस्तेमाल किए जाने को लेकर ईरान से अरबों डॉलर का भुगतान करने को कहा है।

भारतीय जहाज के कैप्टन और चालक दल को लाल सागर बचाव मिशन में अभूतपूर्व साहस के लिए अवार्ड

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लंदन/भाषा। तेल टैंकर के कैप्टन अशिलका रायत और उनके चालक दल को लाल सागर बचाव मिशन में उनके साहस और समुद्र में बहादुरी के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) 2024 पुरस्कार विजेता के लिए नामित किया गया है। अग्रिशमन और शक्ति नियंत्रण प्रयासों के सन्मन्य के

दौरान दृढ़ संकल्प और धीरज का प्रदर्शन करने पर आईएमओ ने रायत और उनके चालक दल को बृहदार को वर्ष 2024 के लिए विजेता घोषित किया। वर्ष की शुरुआत में ईरान समर्थित हूदी विद्रोहियों द्वारा कथित तौर पर दाम्गी गई जहाज-रोधी मिसाइल के उनके जहाज 'मॉर्निंग लुआंडा' पर गिरने से भीषण आग लग गई थी। भारतीय नौसेना के जहाज आईएमओ विशाखापत्तनम के कैप्टन बृजेश नांबियार और चालक

दल को भी संकट के समय तेल टैंकर की सहायता करने के लिए नामांकन प्राप्त हुए। नामांकनों की शुरुआत में मूल्यांकन पैनल द्वारा समीक्षा की और उनकी सिफारिशों पर न्यायाधीशों के फैसले का विचार किया। इसके बाद विजेताओं का चयन किया गया।

न्यायाधीशों के फैसले की सिफारिशों को अब आईएमओ परिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया है, जिसका 132वां सत्र इस सप्ताह लंदन में आयोजित हो रहा है।

फ्लोरेंस में किसी ने हमारा पासपोर्ट, नकदी चोरी कर ली : दिव्यांका त्रिपाठी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। इटली के फ्लोरेंस शहर में छुट्टियां मनाते हुई टीवी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया की गाड़ी की खिड़की का शीशा तोड़कर उनके पासपोर्ट, नकदी और क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड चोरी कर लिये गये। त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को फ्लोरेंस से ही फोन पर 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि वे प्राथमिकी दर्ज करवा रहे हैं और मदद के लिए भारतीय दूतावास से भी संपर्क कर रहे हैं। त्रिपाठी और दहिया फ्लोरेंस के निकट एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं जहां पर्यटन शहर से वाहन से पहुंचने में आधे घंटे का समय लगता है। उन्होंने बताया कि यह घटना बुधवार को स्थानीय समय के अनुसार दोपहर में हुई। टीवी धारावाहिक 'ये है मोहब्बत' से लोकप्रिय हुई अभिनेत्री ने बताया कि इस घटना के बारे में उन्हें शाम को पता चला। त्रिपाठी ने कहा, "हमने उसी दिन होटल में चेक-इन किया था। होटल प्रबंधन को पता था कि हमारा सामान गाड़ी में है और उन्होंने हमसे कहा भी था कि सामान सुरक्षित रहेगा। चूंकि हमें काफी भूख लगी थी तो हम पहले खाना खाने चले गये। हम भी सामान की सुरक्षा को लेकर निश्चित थे कि क्योंकि यह एक रिजॉर्ट है कोई सड़क नहीं।" अभिनेत्री का कहा कि या तो किसी ने उनके पति और उनकी पीछा कर इस वास्तु को अंजाम दिया या फिर ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। त्रिपाठी ने कहा, "चोरों ने कार की खिड़की का शीशा तोड़ा और पिछली सीट पर रखा सारा सामान ले गए जिनमें पासपोर्ट, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड, नकदी शामिल हैं। यहां इस तरह की घटना से हेरान हुईं। हालांकि, होटल के लोग हमारी मदद कर रहे हैं। होटल और उसके परिसर में सीसीटीवी नहीं है, इसलिए हमने सबूत के तौर पर वीडियो बनाया और तस्वीरें ली हैं।" उन्होंने दावा किया कि शाम छह बजे के बाद कोई भी इटली में प्राथमिकी दर्ज नहीं करवा सकता है।



महालक्ष्मी लेआउट संघ में चातुर्मास विषय पर हुई चर्चा साध्वी नयदर्शाश्रीजी का होगा चातुर्मास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के महालक्ष्मी लेआउट संघ के प्रांगण में प्रतिष्ठाचार्य आचार्यश्री प्रभाकरसुरीश्वरजी की आझानुसार साध्वीश्री नयदर्शाश्रीजी का चातुर्मास होना है। इस वर्ष के

चातुर्मास को लेकर गुरुवार को चिंतामणि चेरिटेबल ट्रस्ट की बैठक आयोजित हुई जिसमें नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया।

नई कमेटी में ट्रस्टी के रूप में नरेश बंबोरी, मनीष बंबोरी, विनोद बंबोरी, भीकमचंद दक एवं महेंद्र बंबोरी शामिल हैं। विनोद भंसालील निलेश लोडाल चेतन झारपुथाल

राकेश दांतेवाडिया, दिनेश छाजेड, पंकज गांधी, जवाहर रमानी, जीतू दक, दीपक परमार, सुनील बंबोरी, महावीर बडेरा, विनोद दक, बाबूलाल गितुडिया, गौतम बोहरा एवं अनिकेत बंबोरी को कार्यकारिणी समिति में शामिल किया गया। धनंजय गुरु ने बैठक में चातुर्मास गतिविधियों की रूपरेखा रखी, जिस पर विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।



विशाखापतनम स्टील प्लांट को पुनर्जीवित करना संभव, प्रधानमंत्री लेंगे निर्णय : कुमारस्वामी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

विशाखापतनम स्टील प्लांट के निजीकरण की संभावना को खारिज करते हुए केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि प्लांट को पुनर्जीवित करने की संभावना है और इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। उन्होंने संयंत्र का दौरा करने के बाद मीडियाकर्मियों से कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को पुनर्जीवित करने की संभावना है।

उन्होंने प्रबंधन, ट्रेड यूनियनों के नेताओं और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बारे में गहन चर्चा की है, साथ ही कई सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा, आखिरकार हम उच्च अधिकारियों के साथ कोई निर्णय लेने जा रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि वे संयंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए एक नोट तैयार कर रहे हैं और इसे प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

उन्होंने कहा, इसे पुनर्जीवित करने की संभावना है। इसके लिए हम और काम कर रहे हैं। टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष पी. श्रीनिवास राव ने कुमारस्वामी से मुलाकात की और कहा कि उन्होंने आशासन दिया है कि परियोजना को पुनर्जीवित और संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने अनुरोध किया कि वीएसपी की भूमि जो केंद्र के पास है, उसे आरआईएनएल को हस्तांतरित किया जाए ताकि कंपनी बैंकों से ऋण प्राप्त कर सके।

20,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का आवंटन तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के साथ विलय उनके द्वारा सुझाए गए अल्पकालिक थे। भाजपा नेता विष्णु कुमार राजू ने कहा कि कुमारस्वामी ने संयंत्र को पुनर्जीवित करने पर निर्णय लिए दो महीने का समय मांगा है।

इससे पहले, कुमारस्वामी ने कहा कि किसी को भी यह उर नहीं होना चाहिए कि इस्पात संयंत्र बंद हो जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन से संयंत्र 100 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों के साथ कारखाने का दौरा किया और उत्पादन क्षमता पर काम करने के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत की। मंत्रियों के साथ विशाखापतनम के सांसद एम. भरत, भाजपा नेता जी.वी.एल. नरसिम्हा राव, स्थानीय विधायक पला श्रीनिवास, वीएसपी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अतुल भट्ट और इस्पात मंत्रालय के संचयक सचिव संजय राय और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

महिला के लिव-इन पार्टनर पर नहीं चल सकता क्रूरता का मुकदमा : केरल हाईकोर्ट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी महिला का साथी जो कानूनी रूप से विवाहित नहीं है, उस पर आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता के अपराध का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने गुरुवार को याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के बाद यह फैसला सुनाया, जो शिकायतकर्ता महिला का लिव-इन पार्टनर था।

अदालत ने फैसला सुनाया, आईपीसी की धारा 498 (ए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए



सबसे आवश्यक बात यह है कि महिला के पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की गई हो। 'पति' शब्द का अर्थ है विवाहित पुरुष, जिससे महिला की शादी हुई है। विवाह से ही कोई व्यक्ति महिला के पति का दर्जा पाता है। विवाह का अर्थ कानून की नजर में विवाह है। कानूनी विवाह के

बिना यदि कोई पुरुष किसी महिला का साथी बन जाता है तो वह आईपीसी की धारा 498 (ए) के तहत 'पति' नहीं कहलाएगा।

आरोप यह था कि याचिकाकर्ता ने मार्च 2023 से अगस्त 2023 तक महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, जबकि वे लिव-इन रिश्तेदारों में थीं। कोर्ट ने कहा कि धारा 498ए के तहत अपराध का मुकदमा चलाने के लिए जरूरी है कि क्रूरता का अपराध पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा किया गया हो।

इसमें कहा गया कि एक पुरुष जो कानूनी विवाह के बिना महिला का साथी था उस पर धारा 498ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।



‘नारी के आगे बढ़ने से घर, समाज और राष्ट्र का होता है निर्माण’ जीतो लेडीज नार्थ जेबीएन वी-कनेक्ट की रेफरल मीट आयोजित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। ‘साधारण से असाधारण बनने की राह में अनेक रोड़े आने के बावजूद आगे बढ़ने वाली शक्ति का नाम ही नारी है। एक आम गृहिणी अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर हर चुनौती को पार कर लेती है।’ यह विचार वैवाहिक रिश्ते करवाने वाली ‘जय माता दी’ कंपनी की संस्थापिका अर्चना जैन ने जीतो चेंटर के अंतर्गत जीतो लेडीज

विंग द्वारा संचालित जीतो बिजनेस नेटवर्क जेबीएन रेफरल मीट वी कनेक्ट में व्यक्त किए। उन्होंने जीतो द्वारा आयोजित विविध विषयों की चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कभी योगा, स्पोर्ट्स, कभी बैंकिंग का और छोटे-छोटे लघु उद्योग लगाने के लिए समय-समय पर प्रेरित करती हैं। जेबीएन का यह उद्देश्य है कि मिलो और आगे बढ़ो, आप जितना मिलोगे, जितना नेटवर्क बढ़ाओगे, जितना आप आगे बढ़ेंगे। आर्थिक सुदृढ़ बनना जरूरी है। अपने बिजनेस

हेतु आत्मविश्वास का स्तर बढ़ाए तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें। अपनी बेटियों को पैरों पर खड़ा रहने का आत्मविश्वास दीजिए और फिर जीवन साथी ढूँढिये। एक नारी के आगे बढ़ने से वह घर आगे बढ़ता है घर से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण।

जेबीएन के आठ मिनट प्रस्तुति लैब ग्रोन डायमंड की सुमन रांका (शुद्ध कैरेट) लैब में विकसित हीरे की जानकारी देते

हुए कहा कि हीरा एक अनमोन रत्न है। यही वजह है कि किसी भी बेहतर व्यक्ति या चीज की तुलना हीरे से की जाती है। उन्होंने हीरा खरीदने पर सावधानी बरतने के मुख्य बिन्दु बताये।

इंदरचंद बोहरा, महामंत्री सुधीर गादिगा, संयोजक कमल पुनमिया ने शुभकामना दी। जेबीएन टायकूस के विकेश जैन, किरण जैन, प्रवेश जैन, क्षितिज धारिवाल उपस्थित रहे एवं उनके आगामी कार्यक्रम की सूचना दी। बैठक में 15 रेफरल तथा वन-

टू-वन की कुल संख्या 155 रही। अध्यक्ष सुमन रांका ने सभी का स्वागत किया। सचिव सीमा शाह ने धन्यवाद दिया। उपाध्यक्ष पिकी मेहता ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। जेबीएन बिन्दु मेहता एवं निर्मला सुराणा ने अपने-अपने व्यवसाय के स्टॉल रखे। लेडीज विंगनार्थ अध्यक्ष बिन्दु रायसोनी, उपाध्यक्ष रेश्मा पुनमिया, महामंत्री सुमन वेदमथा, कोषाध्यक्ष मधु कटारिया, रक्षा छाजेड, सोमना सिसोदिया, मनीषा दोशि, पूर्ण जेबीएन मंत्री तनुजा मेहता आदि उपस्थित थीं।

गुरु के प्रति शिकायत नहीं, समर्पण बढ़ाएं : साध्वी अर्चनाश्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैसूरु। आचार्य रामेशजी की शिष्या साध्वीश्री अर्चनाश्रीजी ने शहर के नजरबाद स्थित समता भवन में प्रवचन में गुरु के प्रति अदृष्ट समर्पण की विवेचना करते हुए एकलव्य के एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि गुरु द्वारा तिरस्कार किए जाने पर भी उसकी श्रद्धा में कोई नहीं आई, उसी प्रकार हम

सभी अपने गुरु एवं संघ के प्रति अदृष्ट श्रद्धा और समर्पण के भाव बढ़ें।

इस मौके पर स्थानकवासी संघ के अध्यक्ष सुभाषचंद्र घोका, साधुमार्गी संघ मैसूरु अध्यक्ष सुरेशकुमार दक, उपाध्यक्ष नेमीचंद श्रीमाल, समता युवा संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनिल पोरवाड, युवा संघ अध्यक्ष दिलीप नंदावत महिला, मंडल अध्यक्ष उमा गन्ना, कोषाध्यक्ष श्यामलाल गन्ना आदि उपस्थित रहे।

‘गिग वर्कर’ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी और सामाजिक सुरक्षा योजना की जरूरत : कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने कर्नाटक में ‘गिग वर्कर’ की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विधेयक को ऐतिहासिक कदम करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इन कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की एक कानूनी एवं सामाजिक सुरक्षा योजना की जरूरत है। कर्नाटक सरकार ने ‘कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2024’ का मसौदा पिछले महीने पेश किया था। काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों, खासतौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए डिलीवरी का काम करने वाले लोगों को गिग वर्कर कहा जाता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “यह एक ऐतिहासिक कानून होगा जो राज्य में प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर को औपचारिक रूप से अधिकार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।”

उनका कहना है कि इस कानून के तहत गिग वर्करों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

कोष की स्थापना, गिग वर्करों के मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से रखने के लिए गिग वर्कर कल्याण बोर्ड की स्थापना, सभी गिग वर्करों का सरकार के पास अनिवार्य पंजीकरण जैसे कदमों का प्रावधान किया गया है।

रमेश ने कहा, “लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के समय से भारत के गिग वर्कर की आवाज मजबूती से उठा रहे हैं। तेलंगाना और कर्नाटक की कांग्रेस सरकारों एवं राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार ने गिग वर्कर को न्याय दिलाकर अल्पकालिक कानून बनाए। गिग वर्करों के लिए सामाजिक सुरक्षा भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के न्याय पत्र द्वारा दी गई एक प्रमुख गारंटी थी।”

उन्होंने कहा, “राज्य सरकारों से जितना बने करें लेकिन गिग वर्कर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कानूनी और सामाजिक सुरक्षा योजना की आवश्यकता है। उनकी संख्या 2022 में 77 लाख थी, जो बढ़कर 2030 में लगभग 2.4 करोड़ होने का अनुमान है।” रमेश ने कहा, “गैड केंद्र सरकार के पाले में है। उम्मीद है कि आगामी बजट में इस दिशा में सार्थक कदम उठाए जाएंगे।”

तमिलनाडु में 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 125 से अधिक मत्स्य पालन परियोजनाएं शुरू करेगी केंद्र

नयी दिल्ली। मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह शुक्रवार को तमिलनाडु के मदुरै में आयोजित होने वाले मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन सम्मेलन में 125 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत ये पहल 100 करोड़ रुपये से अधिक के कुल निवेश को दर्शाती हैं। केंद्र सरकार की प्रमुख योजना पीएमएसवाई का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि, विशिष्ट वित्तीय सहायता का विवरण नहीं बताया गया लेकिन उम्मीद है कि इस योजना से स्थानीय व्यवसायों को काफी बढ़ावा मिलेगा और देश के मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि विविध प्रकार की पहलों में मछली खुदरा कियोरक, झिंगा हैचरी, ब्रूड बैंक, सजावटी मछली इकाइयां, बायोप्लॉक इकाइयां, मछली चारा मिलें और मछली मूल्य वर्धित उद्यम शामिल हैं।

जागरुकता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत



बेंगलूरु में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बृहत् बेंगलूरु महानगरपालिका द्वारा जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को विवेकानंद उच्च प्राथमिक विद्यालय विजयनगर में डीबीएमपी के स्वास्थ्य कर्मियों ने डेंगू बीमारी के लक्षण के बारे में बताते हुए बच्चों को लापरवाही न बरतने के लिए जागरुक किया। इस अवसर पर महेंद्र मुणोत एवं विद्यालय के शिक्षक उपस्थित थे।



‘धर्म-प्रवचन है साक्षात् सरस्वती’ बुद्धि-वीर वाटिका में हुआ धर्मसभा का शुभारंभ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैसूरु। शुक्रवार से नजरबाद स्थित बुद्धि-वीर वाटिका, शिक्षक सदन चातुर्मास कार्यक्रम स्थल में नियमित धर्मसभा का शुभारंभ हो रहा है। नियमित चातुर्मास प्रवचनों के पहले गुरुवार को आचार्यश्री विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि प्रवचन जीवन-पथ का आवश्यक पाथेय है।

वैचारिक क्रांति और जीवन परिवर्तन का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता है। जैसे भोजन से भूख मिटती है, उसी तरह धर्म के प्रवचनों से चित्त परितृप्त बनता है। भावदशा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। युगों-युगों की विषय-वासनाओं से मनुष्य ऊपर उठता है।

जन्मोजन्म के राग-द्वेष और कषायों से परिष्कृत होने की प्रेरणाएं मिलती हैं। प्रवचनों की महत्ता और उपयोगिता पर चर्चा करते हुए जैनाचार्य ने कहा कि धर्म, अध्यात्म के प्रेरक प्रवचन साक्षात् सरस्वती है। जो जीवन में कहीं सीखने नहीं मिलता, वह ज्ञान, विद्या, भक्ति, भावना और प्रेरणाओं का बेशकीमती खजाना प्रवचनों से उपलब्ध होता है। वैदिक, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के साहित्य में संतों के समागम और धर्मशास्त्रों के वचनों से मनुष्य के मार्मिक परिवर्तन के हजारों-हजारों प्रसंग उपलब्ध हैं। मनुष्य के भीतरी अंधकार को दूर करने के लिए प्रवचन प्रदीप की भूमिका निभाते हैं।

समय-समय पर सुषुप्त मन को ज्ञानदीपक से प्रज्वलित करके ही हम जीवन के ध्येय को

सार्थक कर सकते हैं। आचार्य विमलसागरसूरीश्वर ने आगे कहा कि अपने 42 वर्षों के संन्यास काल में मैंने हजारों जिवदियों को प्रवचनों से परिलीनित होते हुए नजरों से देखा है। लोगों में अकल्पनीय बदलाव देखे हैं। टूटते घरों को जुड़ते देखा है। आत्महत्या की राह से लोगों को मुड़ते देखा है। व्यसनमुक्ति और शाकाहार को अपनाते देखा है।

लड़ाईयों को शांति में तब्दील होते देखा है। इससे सद्बिचारों और धर्मशास्त्रों के वचनों में भेरा शिक्षास और अधिक मजबूत हुआ है। भारतीय धार्मिक साहित्य परिवर्तन की गौरवगाथाओं से ओतप्रोत है। कल्याण मित्र वर्षावास समिति के कालीलाल चौहान ने बताया कि शुक्रवार से प्रवचनों का समय प्रातः 9 से निर्धारित किया गया है।



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

गुरुदर्शन

पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के संस्थापक योग गुरु स्वामी रामदेव व आचार्य बालकृष्ण ने हृदयवत्ती में पतंजलि वेल्नेस सेन्टर का दौरा किया और मुथा वागमल भुराजी बाफना परिवार से मिले। इस मौके पर बाबा रामदेव ने स्वस्थ जीवन की दिनचर्या बताते हुए योग, प्राणायाम, ध्यान के बारे में बताया। इस अवसर पर एमडब्ल्यूवी गुप के उकचंद बाफना, रमेश बाफना, गौतम बाफना आदि ने स्वामीजी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।